



परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 03, अंक 201, नई दिल्ली, रविवार 28 सितम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

हार तो हर कोई मान लेता है, ये सबसे आसान तरीका है, जीतता वही है जो अंत तक लड़ता है।

03 राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनिन द्वारा विश्व पर्यटन दिवस समारोह आयोजित

06 दुनिया का चेहरा आज परत दर परत कृत्रिमता से ढका हुआ है

08 'एक शाम मां भगवती के नाम' जागरण सम्मन्

सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार ई वाहन को व्यावसायिक गतिविधि में चलाने के लिए राज्य सरकार के परिवहन विभाग से किसी भी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं, क्या यह अधिसूचना दिल्ली में लागू नहीं होती ?

संजय बाटला

दिल्ली परिवहन विभाग अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति सम्पूर्ण संसार में सबसे अधिक प्रसिद्धि पा चुका है पर उसकी प्रसिद्धि के कारण और किए जा रहे कार्यों की गूँज दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय, गृहमंत्री एवम प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के पास नहीं पहुंच पा रही है, आखिर क्यों और कैसे, बड़ा सोचनीय मुद्दा!

जी हां, यह हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं इसके पुख्ता सबूत कोई भी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

दिल्ली परिवहन विभाग विश्व का पहला ऐसा विभाग

1. जो अपने खर्चों में कटौती करने के लिए जनहित का नाम लेकर जनता को राजपत्रित अधिसूचना द्वारा प्राप्त सुविधाओं क्षेत्रीय कार्यालयों को बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर देता है,
2. जो महिला सुरक्षा के नाम से गृह मंत्रालय



सचिव के नेतृत्व में निर्मित कमेटी के द्वारा जारी आदेश पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की जगह दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों से कई सालों तक लुट करवा कर महिला सुरक्षा का नाम कर दिखाता है,
3. जो सर्विस बुक द्वारा जारी आरआर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली, माननीय कैट और विधि

और न्याय विभाग दिल्ली सरकार के द्वारा जारी निर्देशों, परामर्शों को दरकिनार कर तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त कर देता है,
4. ई वाहन निर्माता द्वारा जांच एंजंसी द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर वाहन निर्मित करने और दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा उसको दिल्ली में बेचने से पहले टाइप स्टेट अप्रूवल और ट्रेड

सर्टिफिकेट लेने के बाद भी पंजीकृत नहीं करवा पाता क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग परमिट का नाम लेकर पंजीकरण करने से रोक रहा है,
5. जो किसी कम्पनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसका टेंडर पीरियड समाप्त होने के बाद भी बिना गिनती के कई सालों तक एक्सटेंशन देता आ रहा है,
6. जो व्यवसायिक गतिविधि में शामिल

वाहनों के मालिकों को परेशान करने के उद्देश्य से और एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से वाहन जांच केंद्र में क्षमता ना होने के बावजूद वाहनों को वही से जांच आदेश जारी कर देता है, यह तो कुछ कार्य हैं जो याद करवाए गए हैं लेकिन अगर देखा जाए तो इससे भी बड़ी लिस्ट अभी दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की बाकी हैं पर फिर भी सभी कार्यवाही करने वाली एंजंसीयों, राजनेता, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, एवम गृह मंत्रालय भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय है चुप।

“क्या इसे ही कहते हैं जनहित और जनहित के लिए जनता को प्रदान सरकारी विभाग, बड़ा सवाल ?

रक्षा गरबा- डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव

स्टॉल प्रस्ताव:
सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000
कॉर्नर साइड स्टोल : 3500
तीन साइड ओपन स्टोल : 4500
सिर्फ एक टेबल : 1000
सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण:
रक्षा गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

कार्यक्रम विवरण:
रक्षा गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत मानव अधिकार उल्लंघन की समस्या – वैश्विक परिदृश्य

पिकी कुंडू :- सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश भाजपा

1. राजनीतिक दमन (Political Repression):- अधिनायकवादी शासन (authoritarian regimes) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार पर अंकुश। उदाहरण: कई देशों में पत्रकारों, एक्टिविस्टों और विपक्षी नेताओं की हत्या या गिरफ्तारी।

2. युद्ध और सशस्त्र संघर्ष (Wars & Armed Conflicts):- *सीरिया, यमन, गाजा, यूक्रेन जैसे संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों पर हमले। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (Geneva Conventions) का बार-बार उल्लंघन।

3. जातीय और धार्मिक भेदभाव (Ethnic & Religious Persecution)
१. म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार।
२. अफ्रीकी देशों में जनसंहार (genocide) जैसी घटनाएं।

* अल्पसंख्यक समुदायों का दमन।
4. शरणार्थी और प्रवासी संकट (Refugee & Migration Crisis)

१. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 तक दुनिया में 11 करोड़ से अधिक विस्थापित लोग (displaced persons) हैं।
२. इनमें से लाखों लोग बिना राष्ट्रीयता (stateless) हैं और उनके बुनियादी अधिकार भी नहीं हैं।

5. आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन
१. बाल श्रम, मानव तस्करी, जबरन मजदूरी।



२. स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का अभाव।
३. लैंगिक हिंसा और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव।

सच्चा और जवाबदेही की वास्तविक स्थिति

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर
१. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) शिकायतों की सुनवाई करती है, लेकिन उसके पास प्रत्यक्ष दंडात्मक शक्ति नहीं है।
२. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और जनसंहार (genocide) जैसे मामलों में कार्रवाई करता है।

* लेकिन कई शक्तिशाली देश ICC को मान्यता नहीं देते (जैसे अमेरिका, चीन, रूस)।
2. क्षेत्रीय मानवाधिकार निकाय (Regional Mechanisms)

१. यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) – यूरोप में कई सरकारों को सजा और क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए।
२. अफ्रीकी और अमेरिकी मानवाधिकार आयोग/न्यायालय – सीमित प्रभाव।

* एशिया में कोई मजबूत क्षेत्रीय मानवाधिकार न्यायालय मौजूद नहीं है।
3. राष्ट्रीय स्तर
१. कई देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं (जैसे भारत का NHRC)।
२. लेकिन ये अक्सर “अनुशासा” ही कर पाते हैं, सीधी सजा नहीं दे सकते।

* न्यायपालिका की धीमी प्रक्रिया और राजनीतिक दबाव के कारण दोषियों को बहुत देर से या कभी सजा नहीं मिलती।
4. वास्तविकता (Ground Reality)
१. अधिकांश मामलों में अपराधी बच निकलते हैं, खासकर जब वे राज्य या सेना से जुड़े हों।
२. केवल छोटे या कम शक्तिशाली अपराधियों को ही दंड मिलता है।

* पीड़ितों को न्याय तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, और कई बार न्याय मिलता ही नहीं।
कानून बनाम वास्तविकता
कानून: यूडीएचआर, जिनीवा कन्वेंशन, आईसीसी स्टैट्यूट, और कई राष्ट्रीय संविधानों में मानवाधिकारों की सुरक्षा की गारंटी है।
वास्तविकता: राजनीतिक दबाव, शक्तिशाली देशों की हठधर्मिता और न्यायिक प्रक्रियाओं की

कमजोरी के कारण मानवाधिकार उल्लंघनों पर सजा कम और प्रतीकात्मक ही रह जाती है। पीड़ित की आवाज अक्सर दब जाती है और दोषी “राजनीतिक दाल” के पीछे सुरक्षित हो जाते हैं।
निष्कर्ष मानव अधिकार उल्लंघन आज भी पूरी दुनिया में बड़ी समस्या है।

1. युद्धग्रस्त क्षेत्रों में आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित हैं।
2. शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों के लिए जीवन असुरक्षित बना हुआ है।
3. दंड की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन न्याय और वास्तविक सजा के बीच लंबी दूरी है।

इसलिए जरूरत है:
1. वैश्विक स्तर पर मजबूत और निष्पक्ष मानवाधिकार तंत्र की।
2. ऐसे कानून जिन पर सभी देश बाध्य हों और उनका उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई हो।

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत
www.tolwa.com
tolwaindia@gmail.com
https://www.tolwa.com/mem
ber.html

"टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत" सेवा ही संकल्प है!



पिकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट

हमारा मकसद सिर्फ मदद नहीं, बदलाव लाना है।
A voice for the voiceless, and a hand for the helpless.

हमारा उद्देश्य है समाज के उन हिस्सों तक पहुंचना जो आज भी भूख, शिक्षा और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम जरूरतमंदों को बिना भेदभाव के भोजन, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, और समाज को जागरूकता देने का कार्य कर रहे हैं।
क्या मिलेगा हमसे जुड़कर

Ground-level food distribution, Getting children free education, हम मानते हैं – छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है।
If you believe in humanity, equality, and service — then

you're already a part of our family.
हमें सपोर्ट करें और एक आवाज बनें इस बदलाव की।
Together, let's serve. Together, let's change.
टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फार्म भरकर जुड़े,
www.tolwa.com/member.htm

1 स्कैनर को स्कैन कर के भी आप टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से फार्म भर कर जुड़ सकते हैं, वेबसाइट पर www.tolwa.com पर भी जाकर आप फार्म भर के टोलवा ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं।
www.tolwa.com

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत
tolwaindia@gmail.com
www.tolwa.com

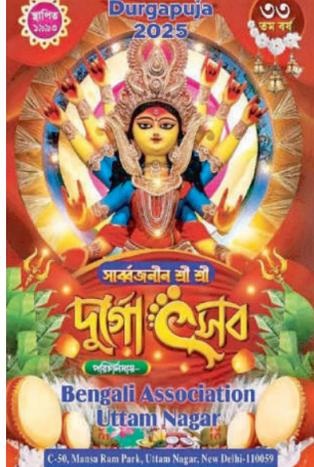
“श्री श्री दुर्गा शरणाम” तैंतीसवां सार्वजनिक दुर्गाोत्सव

प्रिय महोदय,

आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके शहर उत्तम नगर में उत्तम नगर कालीबाड़ी द्वारा शनिवार दिनांक 27 सितंबर, 2025 से 2 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार तक सी-50, मनसा राम पार्क, नई दिल्ली-59 में श्री श्री दुर्गा माँ की पूजा एवम 20 अक्टूबर, 2025 सोमवार श्री श्री काली माँ की पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सबसे हार्दिक निवेदन है कि आप सब इस विशाल आयोजन में सम्मिलित होकर माँ दुर्गा एवम काली माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस आयोजन को सफल बनायें।
प्रिय भक्तों!
हमें आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तम नगर कालीबाड़ी, सी-50, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में 33वें वर्ष दुर्गा पूजा एवं काली पूजा समारोह का आयोजन कर रही है। हम आपके परिवार और मित्रों को 27 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक हमारे काली मंदिर में आयोजित होने वाले इस समारोह में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं।
आइए एक बार फिर खुशियाँ बाँटें, अपनी आत्मा को समृद्ध करें और पारिवारिक माहौल में त्योहार का आनंद लें। आप सभी के उदार सहयोग

और भागीदारी को हम बहुत सराहना करते हैं। दुर्गा पूजा पर और हमेशा आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।

भवदीय
उत्तम नगर कालीबाड़ी,
मलय डे (अध्यक्ष)
7217666618
जयंत डे (सचिव)
9654385888
पिकी कुंडू (सदस्य)
पूजा कार्यक्रम-2025
27 सितंबर 2025, (शनिवार)।



बोधन
28 सितंबर 2025, (रविवार)
षष्ठी आमंत्रण और अधिवास
29 सितंबर 2025, (सोमवार)
सप्तमी पूजा
30 सितंबर 2025, (मंगलवार)
अष्टमी और संधि पूजा
1 अक्टूबर 2025, (बुधवार)
नवमी पूजा
2 अक्टूबर 2025, (गुरुवार)
दशमी पूजा और विसर्जन
पुष्पांजलि 11.00 बजे से 1:00

बजे तक,
प्रसाद वितरण 1.00 बजे से 1:30 बजे तक,
भोग वितरण 1.30 बजे से 3.00 बजे तक।
संध्या आरती- 7.00 बजे
श्री श्री काली पूजा सोमवार, 20 अक्टूबर, 2025
कार्यक्रम का स्थान:
कालीबाड़ी, सी-50, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

You're Invited!

Anandomela Food Fiesta 2025

Celebrate the spirit of Durga Puja with food, fun, and festivity!

Join us at our much-awaited Anandomela Food Fiesta, where the aroma of tradition meets the joy of celebration! Bring your favorite homemade delicacies, share your culinary skills, and enjoy a vibrant evening with your community.

Date: 28.09.2025
Venue: KALI BARI (uttam nagar)
Time: 7.00PM

Whether you're a seasoned cook or just love feeding people, we welcome your participation with open arms!

For stall bookings and participation details,
Please contact:
Mrs.Pinki Kundu- 7053533169
Mrs.Tithi Ghosh- 9013088489

Let's make this Durga Puja even more delicious and memorable!

Regards
Jayant Dey
General Secretary

मोती नगर इलाके के कैलाश पार्क में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग.....

परिवहन विशेष न्यूज

27/9/25 दिल्ली मोती नगर इलाके के कैलाश पार्क में सुबह 9:30 बजे बजे के करीब मेट्रो पिलर नंबर 335 के सामन कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग

पब्लिक ने बताया कि तीन एलपीजी के सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ है गृहे के कबाड़ का गोदाम था एमसीडी की जगह कब्जा करके गोदाम बनाया हुआ है 500 गज से भी ज्यादा की जगह में यह गोदाम है यह

जानकारी पब्लिक ने दी कड़ी मेहनत के बाद 10 फायर की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया आपदा मित्र और नागरिक सुरक्षा की टीम ने घाटस्थल से जनाता को हटाया और ट्रैफिक कंट्रोल किया जिसे बचाव कार्य में किसी

प्रकार की दिक्कत न आए मौके पर स्थानीया पुलिस आपदा प्रबंधन की टीम आपदा मित्र दिल्ली नागरिक सुरक्षा बिजली विभाग की टीम मौजूद थी 12-00 बजे के करीब आग पर पूरी तरह से कबु पया गया।

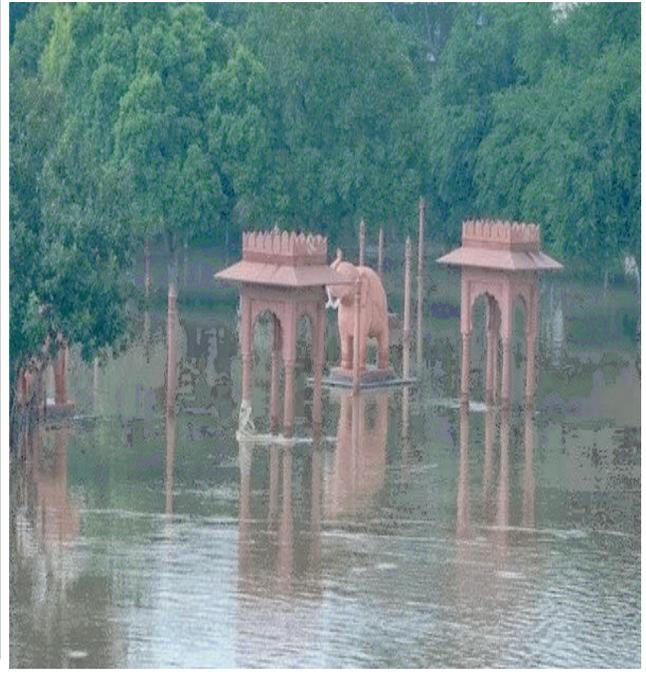


बिना पूर्ण जांच पड़ताल किए जनता का पैसा डीडीए द्वारा खर्च करना कितना सही ?

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में कुछ ही महीने पहले यमुना नदी ने रोड़ रूप दिखाया था, जिसके कारण नदी किनारे बने कई जगह पानी में डूब गए थे। अब लगता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) उन सबक को भुलाकर एक बार फिर करोड़ों रुपये खर्च करने की

तैयारी में है। एक्सपर्ट्स की तमाम चेतावनियों के बावजूद, DDA ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह यमुना किनारे के अपने दो प्रमुख घाटों - असिता (Asita) और वासुदेव (Vasudev) घाट पर मरम्मत और रखरखाव का काम फिर से शुरू करने जा रहा है।



भारत के गेमिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एसुस आरओजी ने क्रोमा दिल्ली में आरओजी शोडाउन का आयोजन किया।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: भारत के अग्रणी गेमिंग ब्रांड, एसुस रिपब्लिक ऑफ गेमर्स (आरओजी), ने आज क्रोमा, ओडियन सीपी में - आरओजी शोडाउन - का आयोजन किया। यह आयोजन उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में नवीनतम है, जिनका उद्देश्य कम्युनिटी की भागीदारी को मजबूत बनाना और प्रतिस्पर्धी ई-स्पोर्ट्स को युवा गेमर्स के लिए अधिक सुलभ बनाकर भारत में गेमिंग इकोसिस्टम का विस्तार करना है।

इस संस्करण में वैलोरेंट (2v2 फॉर्मेट) शामिल था, जो युवा गेमर्स के बीच सबसे लोकप्रिय गेम में से एक है। टूर्नामेंट में 120 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, 60 टीमों ने भाग लिया

और लाइव दर्शकों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए जमकर तालियाँ बजाईं, जिसे आयोजन स्थल पर एक रोमांचक माहौल बन गया।

इस पहल के बारे में बात करते हुए, एसुस इंडिया के एलएफआर मैनेजर परेश कपाड़िया ने कहा, "आरओजी शोडाउन के माध्यम से, हम न केवल गेमिंग प्रेमियों को प्रतिस्पर्धा करने और अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर प्रदान कर रहे हैं, बल्कि भारत में ई-स्पोर्ट्स के लिए एक मजबूत समुदाय भी बना रहे हैं। क्रोमा जैसे पार्टनर रीटेल स्टोर में टूर्नामेंट आयोजित करने से प्रतिस्पर्धी गेमिंग का रोमांचक उभारों के और करीब पहुंचता है, साथ ही उन्हें आरओजी डिवाइस की पूरी क्षमता का



अनुभव करने का मौका भी मिलता है। यह भारत के गेमिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने और अगली पीढ़ी के गेमर्स से जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" क्रोमा में आरओजी शोडाउन के बारे में बात करते हुए, क्रोमा के एक प्रवक्ता ने कहा,

"भारत में गेमिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और इस विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हम उत्साहित हैं। हमारे ओडियन, कर्नाट प्लेस स्टोर में

आरओजी शोडाउन का आयोजन करना, सिधे हमारे ग्राहकों को रोमांचक और ऊर्जावान अनुभव प्रदान करने की हमारी कोशिश का एक हिस्सा है। आजकल गेमिंग कई युवा भारतीयों के लिए एक करियर पाथ और जीवन भर की लगन बन गया है। एसुस

आरओजी जैसे ब्रांडों के साथ सहयोग करके, हम ऐसे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो अत्याधुनिक तकनीक को प्रदर्शित करते हैं और ई-स्पोर्ट्स को अधिक सुलभ बनाते हैं।"

विजेताओं को ₹35,000 का पुरस्कार मिला, जबकि उप-विजेताओं को ₹15,000 प्राप्त हुए। इस प्रतियोगिता के विजेता श्री संभव सिंह और श्री तुषार सिंह (उपविजेता) श्री सुरश और श्री अमन सिंह असवाल थे। इस तिमाही में ही 24 सफल शोडाउन के आयोजन के साथ - जिसमें छह लार्ज फॉर्मेट रीटेल (एलएफआर) स्टोर शामिल हैं, आरओजी आगे भी ऐसे रोमांचक अनुभव प्रदान करता रहेगा जो ई-स्पोर्ट्स और रीटेल सहभागिताओं को एक साथ जोड़ते हैं।



आज राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन द्वारा कुतुब मीनार पर विश्व पर्यटन दिवस समारोह आयोजित किया गया।

सदर बाजार जाम को लेकर व्यापारियों व ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की बैठक



मुख्य संवाददाता

दिल्ली: त्योहारों को देखते हुए डीसीपी ट्रैफिक सेंटर रजिशांत गुप्ता ने ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर अधिकारियों का व्यापारियों की एक बैठक बुलाई जिसमें इंस्पेक्टर, सुधीर टीआई, एसबीसी सहित अनेक ट्रैफिक अधिकारी व व्यापारी नेता सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पन्ना, आजाद मार्केट क्रोकारी मार्केट के टोनी, नरेश महाजन अध्यक्ष आजाद मार्केट, व्यापारी नेता हरजीत सिंह छाबड़ा सहित अनेक व्यापारी उपस्थित थे जिन्होंने सदर बाजार, आजाद मार्केट की ट्रैफिक की समस्याओं से डीसीपी साहब को अवगत कराया।

इस अवसर पर परमजीत सिंह पन्ना ने डीसीपी साहब निशांत गुप्ता को बताया सदर बाजार थाने से लेकर 12 ट्यूटी चौक तक जो एमसीडी ने पार्किंग दी हुई है वह वहां पर दो-तीन लाइन गाड़ियां लगा देता है जिससे आए दिन जाम लगा रहता है। इसके साथ ही सभी सदर बाजार, आजाद मार्केट चौकों पर ई-रिक्शा वाले पुर चौक जाम

कर देते हैं। उन्होंने डीसीपी साहब से निवेदन किया कि वह पिक एवर पर मिठाई पुल चौक, 12 ट्यूटी, सदर थाना, कुतुब रोड, तेलीवाड़ा पर सुबह 9:00 से 11:00 तक शाम को 6:00 से 9:00 तक जर्जर ट्रैफिक स्टाफ उपलब्ध कारण। जिससे आने वाली समय में काफी समस्या हल हो जाएगी।

परमजीत सिंह पन्ना ने कहा जिस प्रकार आने वाले समय में त्योहारों का है मार्केट में सामान खरीदने वालों की भीड़ भी बढ़ेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का ज्यादा स्टाफ तैनात किया जाए।

इस अवसर पर डीसीपी साहब निशांत गुप्ता ने व्यापारियों को आशवासन दिया कि वह जल्द ही व्यापारियों की समस्या हल करेंगे और दशहरे के बाद ज्यादा स्टाफ मार्केट में ट्रैफिक पुलिस का बढ़ाया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से भी निवेदन किया कि वह कोई भी रोड पर गाड़ी ना खड़ी करें और वह सुबह शाम ट्रैफिक अधिकारियों को भी हर चौक पर तैनात करेंगे।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने मनाया हिन्दी उत्सव

हमें सदैव अपनी माँ, मातृभूमि और अपनी भाषा के प्रति निष्ठावान और ईमानदार होना चाहिए:- प्रो. कैन

नई दिल्ली। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी उत्सव में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, मुख्यालय नोएडा में रमण शिखा के द्वारा ही भावी शिक्षा की दिशा निर्धारित होगी विषय पर अंतर्विभागीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में - डॉ. आलोक कुमार गुप्ता, उप निदेशक (प्रशा.), डॉ. इंद्रजीत सिंह, निर्माण सहायक ने प्रथम; डॉ. अविनाश त्रिपाठी, शैक्षिक अधिकारी, श्रीमती उमंग चौहान, शैक्षिक अधिकारी ने द्वितीय; श्री चुन्नु प्रसाद, सहायक निदेशक, श्री अतुल कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी ने तृतीय स्थान; श्री अदिति रंजन राउत, श्री बी. सतीश, डॉ. अंचल गोस्वामी, श्रीमती सुनीता रानी ने प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किए।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी विशेषज्ञ प्रोफेसर मनोज कुमार कैन उपस्थित रहे। प्रो. मनोज कुमार कैन दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मुख्य अतिथि का स्वागत उप -



निदेशक श्री राजेश गौतम ने किया (कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉ. आलोक कुमार गुप्ता ने प्रो. कैन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। प्रो. कैन ने पुरस्कार प्राप्त प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि आज वर्तमान सरकार हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। निरंतर हिंदी की उन्नति और प्रगति के लिए

कार्य कर रही है। सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन पर बल दिया गया है। सरकार के प्रयासों से विश्व में भारत और हिंदी भाषा की एक अलग पहचान बनी है। उन्होंने कहा हमें सदैव अपनी माँ, मातृभूमि और अपनी भाषा के प्रति निष्ठावान और ईमानदार होना चाहिए।

प्रो. कैन ने हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में हिंदी अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमारी चौहान ने बताया कि एनआईओएस मुख्यालय के साथ-साथ पूरे भारत में स्थित इसके 20 क्षेत्रीय केंद्रों में भी विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं

कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज की प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। आश्री सिन्हा, डॉ. अलका सिंह, अर्चना वर्णमाल, अलका तिवारी, सुशील कुमार, राजीव कुमार, बालम गिरी, पंकज पाल आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह आयोजन सफल और सार्थक रहा।

दिल्ली के विकास मिश्र को लखीमपुर खीरी में मिलेगा "गोमती साहित्य सम्मान 2025"

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

दिल्ली। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बे मोहम्मदी में भारत की प्रतिष्ठित संस्था कथाकुंज साहित्य सेवा परिषद के द्वारा कथाकुंज के संरक्षक प्रो. सुदीप कुमार की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन व सम्मान समारोह का आयोजन 7 अक्टूबर 2025 को बड़े ही हार्मोल्लास एवं धूमधाम के साथ आयोजित किया जायेगा।

इसमें शामिल साहित्यकारों को क्रमशः रकेतकी साहित्य रत्न सम्मान 2025 (महिला) व रंगोमती साहित्य रत्न सम्मान 2025 (पुरुष) का प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कृषि राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा राज व विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकेंद्र प्रताप सिंह सभापति (राज्यमंत्री) एवं पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश तथा

संदीप मेहरोत्रा (पालिकाध्यक्ष, मोहम्मदी) उपस्थित रहेंगे।

ज्ञात हो कि संस्था के द्वारा पिछले 3 वर्षों में 50 से भी अधिक साहित्यकार इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं।

संस्था अध्यक्ष गोविंद गुप्त ने बताया कि इस वर्ष भी पूरे देश से चयन किया गया है। इस वर्ष पुरुषों में रंगोमती साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित होने वाले कवियों में दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में कार्यरत विकास मिश्र को संस्था द्वारा चयनित किया गया है जो मूलतः ग्राम नटोली, कला ब्लॉक कुरेभार, सुल्तानपुर (उ.प्र.) के निवासी हैं। पूर्व में वे राम राजी डियरी कॉलेज, वैदहा में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर, शास्त्री बाल विद्या मंदिर, मोतीगंज में अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता, सुदनापुर बाजार में आकाश कोचिंग सेंटर के प्रबंधक, शांती

देवी बाल शिक्षण संस्थान, बरचवल (कुरेभार) के उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। शिक्षा विभाग से उनका और उनके परिवार का पुराना नाता है। अंग्रेजी विषय और राजनीति शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट विकास मिश्र को कविता और लेखन में विशेष रुचि है। क्योंकि उनके पुत्र्य पिताजी भी मधुसूदन विद्यालय इंटर कॉलेज, सुल्तानपुर में सहायक अध्यापक रहे हैं। पिछले चार वर्षों से विकास मिश्र कविताएं भी लिख रहे हैं। विकास मिश्र अनेक साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय काव्य मंच, मुंबई जिसके वह सचिव एवं प्रवक्ता हैं। वे पत्रकारिता जगत से भी जुड़े हैं। प्रतिष्ठित रॉडि ग्राम टुडे हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में उप संपादक और संस्कार न्यूज में भी वह रोजिडेंट संपादक हैं। कविता लेखन के साथ वह मंचों पर अच्छा संचालन भी करते हैं।



परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com

विविध विशेष

प्रतिभा पलायन को रोकने का बड़ा मौका

प्रो. महेश चंद गुप्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। पहले जहां यह फीस लगभग 80 हजार रुपये थी, वहीं अब इसे 80 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। स्वाभाविक है कि अब पहले जितनी संख्या में भारतीय युवा अमेरिका नहीं जा पाएंगे। इस फैसले से दुनिया भर में उथल-पुथल मची है जिसका फायदा उठाने की कोशिश चीन कर रहा है। उसने ‘के वीजा’ नामक नई श्रेणी की घोषणा की है जिसके तहत वह दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी प्रोफेशनल्स को अपने यहां आकर्षित करना चाहता है। यह वीजा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तकनीक और व्यवसाय के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराएगा।

भारत के लिहाज से यह स्थिति एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों लेकर आई है। चुनौती इसलिए क्योंकि अमेरिकी दरवाजे बंद होने के बाद चीन नए अवसर देकर हमारी प्रतिभाओं को अपने यहां खींच सकता है। अवसर इसलिए है क्योंकि यह भारत के लिए प्रतिभा पलायन रोकने का सुनहरा मौका है। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार, उद्योग जगत और कॉर्पोरेट सेक्टर मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां हमारे युवा देश में रहकर ही अपने सपनों को साकार कर सकें। भारत हमेशा से ही शिक्षा और प्रतिभा के मामले में समृद्ध रहा है पर प्रतिभा पलायन हमारी बड़ी समस्या है। हर साल लाखों छात्र-छात्राएं इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और रिसर्च के क्षेत्र में पढ़ाई पूरी करते हैं लेकिन अफसोस है कि उनमें से बड़ी संख्या में युवा विदेशों का रुख कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में शोध के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, रोजगार के अवसर सीमित हैं और जो अवसर उपलब्ध हैं, उनमें योग्य प्रतिभा को सम्मान और सुरक्षा का अभाव है।

डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और आईटी

प्रोफेशनल विदेश जाकर वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जबकि उनकी प्रतिभा का लाभ भारत को मिलना चाहिए। एक तरफ हम युवाओं की शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, दूसरी ओर वे अवसरों की कमी के कारण देश छोड़ जाते हैं। यह भारत के विकास के लिए बड़ी हानि है। ट्रंप का वीजा फीस वृद्धि का कदम दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का विषय हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि भारत को इसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। जब अमेरिका में वीजा इतना महंगा हो गया है कि आम युवा वहां नहीं जा पाएंगे तो इससे स्वाभाविक रूप से प्रतिभा पलायन पर अंकुश लगेगा। यह स्थिति भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इस मौके का उपयोग भारत कर पाएगा? अगर सरकार और उद्योग जगत ने युवाओं के लिए बेहतर माहौल तैयार किया तो वे भारत में ही रहकर काम करना पसंद करेंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह संभावना है कि निराश युवा चीन की ओर आकर्षित हो जाएं।

चीन ने हालात को भांपते हुए तेजी से ‘के वीजा’ का विकल्प प्रस्तुत किया है। इस वीजा के माध्यम से वह दुनिया भर की प्रतिभाओं को अपने यहां शिक्षा, रिसर्च और बिजनेस में अवसर देने की योजना बना रहा है। ऐसा करके वह वैश्विक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नेतृत्व के अपने लक्ष्य को पूरा करने की तमन्ना रखता है। यदि भारतीय युवा अमेरिका के बजाय चीन का रुख करने लगे तो यह हमारे लिए और भी गंभीर स्थिति होगी क्योंकि एक तरफ तो भारत अपनी ही प्रतिभा से वंचित रह जाएगा और दूसरी ओर चीन हमारी ही ताकत का उपयोग करके आगे निकलने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में हमें गहरा आत्म चिंतन की जरूरत है। इस समय यह बड़ा सवाल है कि क्या हमारे युवा विदेशों में ही अपनी क्षमता साबित करेंगे या फिर देश में रहकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? इसका उत्तर देश की



नीतियों और कार्यप्रणालियों पर निर्भर करता है।

वर्तमान में विश्व की टॉप 100 कॉर्पोरेट कंपनियों में उच्च पदों पर हमारे युवा हैं, जो उनके कामकाज को पूरे विश्व में फैलाने में सहायक हो रहे हैं। सुंदर पिचई (गूगल), सत्य नडेला (माइक्रोसॉफ्ट), अजय बंगा (विश्व बैंक), अरविंद कृष्णा (आईबीएम) और इंद्रा नूई (पेप्सिको) जैसे दिग्गज भारतीय मूल के लोगों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता यह साबित करती है कि भारतीय मस्तिष्क वैश्विक स्तर पर किसी से कम नहीं है। सवाल यह है कि अगर प्रतिभावान युवाओं को देश में ही जरूरत अवसर और वातावरण मिल जाता तो क्या वे यहीं रहकर भारत को विश्व का नेतृत्व दिला सकते थे? इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से हाँ में है।

देश के युवाओं को पिछले सत्तर साल में जो आधारभूत ढांचा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सुविधाएं, वेतन और अन्य सुविधाएं देनी चाहिए थीं, अगर वह दी गई होती तो प्रतिभा पलायन की स्थिति

न बनती।। हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में हम अब भी कमजोर हैं। और तो और, हमारे पास अपना भरोसेमंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। हम ई-मेल सेवा जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। हमें कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और चिप तकनीकों में आत्म निर्भरता हासिल नहीं हुई है। आज भी हम रक्षा हथियारों व रक्षा उपकरणों, यांत्री यंत्रों, लड़ाकू विमानों आदि के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। कम्प्यूटर व डिजिटली टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्ष, डेटा प्रबंधन, अकाउंटिंग एवं फायनेंस मैनेजमेंट, ऑडिट एवं कन्सल्टेंसी, रिसर्च टेक्नोलॉजी आदि पर हम विश्व टॉप संस्थानों पर पूर्णतया निर्भर हैं। हमें इस स्थिति को तीव्रगति से बदलना होगा अन्यथा, हम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे।

अगर युवा प्रतिभा मौजूद होने के बावजूद यह स्थिति चिंताजनक है। अगर हमारे युवाओं को आवश्यक संसाधन, शोध की सुविधाएं और

आत्मशक्ति, भक्ति और लोककल्याण का महापर्व: नवरात्रि - मां भगवती के चरणों में है जीवन की पूर्णता : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

श्री राजेश खुराना ने मां भगवती से सम्पूर्ण विश्व के सुख, शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना की – कहा, हम सभी यह प्रार्थना करें कि मां दुर्गा की अनंत कृपा मानवता पर निरंतर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से सम्पूर्ण विश्व में प्रकाश, प्रेम और लोककल्याण का विस्तार हो

नवरात्रि : एक अदसर आत्मबोध का, एक संकल्प लोकसेवा का – भक्ति, सेवा और शक्ति के इस पर्व को आंतरिक जागरण के साथ मनाएं

आगरा, संजय सागर सिंह।शुक्रवार को देहली गेट स्थित राजा मंडी रेलवे स्टेशन परिसर में दैनिक यात्री व व्यापारी संघ (पोचा भाई ग्रुप) द्वारा आयोजित मां चामुंडा देवी मेले में वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने भव्य महाआरती कर

मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धा से ओत-प्रोत इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

मां भगवती करुणा की साकार मूर्ति
अपने संदेश में श्री राजेश खुराना ने कहा, रमां भगवती केवल शक्ति की अधिष्ठात्री ही नहीं, अपितु करुणा, प्रेम और लोककल्याण की सजीव प्रतिमूर्ति हैं। उनके चरणों में जीवन की पूर्णता, शांति और संतुलन निहित है। मां दुर्गा की कृपा से जीवन के समस्त क्लेश समाप्त होते हैं और आत्मा को शुद्धि का पथ प्राप्त होता है।

नवरात्रि: आध्यात्मिक यात्रा और आत्मचिंतन का काल

वरिष्ठ समाजसेवी श्री खुराना ने नवरात्रि को आत्मनिरीक्षण, संयम और सेवा का पर्व बताते हुए कहा कि यह समय केवल व्रत और पूजा का नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन से संवाद करने और भीतर की

शक्ति को पहचानने का है। यह पर्व आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है, जिसमें साधक अपनी अंतःशक्ति को जागृत कर उस समाज सेवा में समर्पित करता है।

मांकेनीरूप: साधना सेसिद्धित
श्री खुराना ने कहा कि नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपांकी उपासना साधक को न केवल आध्यात्मिक बल प्रदान करती है, बल्कि मानसिक स्थिरता, आरोग्यता और जीवन में संतुलन भी स्थापित करती है। मां भगवती अपने भक्तों के दु:ख हटाकर उन्हें ऊर्जा और उत्साह से भर देती हैं।

नवरात्रि: लोककल्याण और सामाजिक समरसता का संदेश

सभी नागरिकों से अपील करते हुए श्री खुराना ने कहा, शक्ति, साधना और समाजसेवा का संगम नवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मिक उत्थान और

सामाजिक समरसता का सशक्त माध्यम भी है। हर व्यक्ति को इस पर्व को श्रद्धा, भक्ति और सेवा के संकल्प के साथ मनाना चाहिए। नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह आत्म-शक्ति की पहचान और जनकल्याण की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है।

मां दुर्गा की कृपा सम्पूर्ण विश्व पर बनी रहे
अपने संदेश के समापन में श्री राजेश खुराना ने मां भगवती से सम्पूर्ण विश्व के सुख, शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना की। उन्होंने आगे कहा, हम सभी यह प्रार्थना करें कि मां दुर्गा की अनंत कृपा मानवता पर निरंतर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से सम्पूर्ण विश्व में प्रकाश, प्रेम और लोककल्याण का विस्तार हो। नवरात्रि: एक अवसर आत्मबोध का, एक संकल्प लोकसेवा का – भक्ति, सेवा और शक्ति के इस पर्व को आंतरिक जागरण के साथ मनाएं।

कानपुर में गुरु के घर से लाखों के जेवरत उढ़ाने वाली मुजफ्फरनगर की किन्नर चांदनी की तलाश में छापे

सुनील बाजपेई
कानपुर। यहां अपने गुरु व अन्य साथी किन्नरों के चकेरी स्थित घर से मुजफ्फरनगर में रहने वाली किन्नर चांदनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर लगभग 30 लाख के जेवरत लेकर चंचल हो गई है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने अब उसके गृह जनपद मुजफ्फरनगर में भी जाल बिछाया है। फिलहाल समाचार

लिखे जाने तक उसका सुराग नहीं मिला है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी है।

मिली जानकारी के मुताबिक शातिर किन्नरों ने अपने गुरु माता और डेरे के किन्नरों की हर शीली चाय देकर करीब 30 लाख के जेवरत और कैश उड़ा दिया। हथौते में आने पर किन्नर ने मामले की जानकारी चकेरी थाने में दी।

यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है।

प्राप्त विवरण के मुताबिक सनिगवां केआरपुरम की रहने वाली रेशमा किन्नर किन्नर समाज की गुरु माता है। जो किन्नर के रूप में अपने डेरे में रहती है।

मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़ित किन्नर रेशमा ने बताया कि सुबह 11 बजे

मुजफ्फरनगर की रहने वाली चांदनी किन्नर अपने दो साथियों के साथ उनके डेरे में आईं। कई बार पहले भी वह डेरे में आ चुके थे। इसी दौरान उन्होंने सभी को नशीला पदार्थ पिला दिया और जब बेहोश हो गए तो लगभग 30 लाख के जेवरत लेकर फरार हो गये। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके उनकी तलाश कर रही है।

ट्रंप ने भारत पर फोड़ा टैरिफ बम- दवाओं पर 100 पर्सेंट टैरिफ- वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर विश्लेषण

ट्रंप टैरिफ,ब्रांडेड और पेटेंट वाली फार्मास्युटिकल दवाओं पर लगेगा ,जबकि भारत जेनेरिक दवा उत्पादक और निर्यातक देश है, इस फैसले से भारत प्रभावित नहीं होगा– एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गौडिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को दुनियाँ में नीति-निर्माण अक्सर केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी जुड़ा होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100 पर्सेंट टैरिफ लगाने की जो घोषणा की है, वह इसी तथ्य का प्रमाण है। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। उल्लेखनीय है कि यह टैरिफ उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका के भीतर उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करेंगी। इसका सीधा अर्थ है कि ट्रंप प्रशासन ‘अमेरिका फर्स्ट’ और ‘मेक इन अमेरिका’ की नीति को फार्मास्युटिकल सेक्टर में और मजबूत करना चाहता है। यह कदम न केवल अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों पर असर डालेगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी। किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी पर भी 50 पर्सेंट टैरिफ लगाया-ट्रम्प ने किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और उनसे जुड़े सभी सामानों पर भी टैरिफ लगाया है। उन्होंने कहा- ‘हम 1 अक्टूबर 2025 से, किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और उनसे जुड़े सभी सामानों पर 50, पर्सेंट टैरिफ लगााना शुरू कर देंगे। इसके अलावा, हम अफरोल्टस्ट-एन फर्नीचर (गद्ददार या फ्लोम वला फर्नीचर) पर 30 पर्सेंट टैक्स लेंगे। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गौडिया महाराष्ट्र ऐसा मानता हूँ कि भारत, जो दुनियाँ का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा उत्पादक

और निर्यातक देश है, इस फैसले से विशेष रूप से प्रभावित होगा क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा बाजार है हालाँकि आदेश में जेनेरिक दवाइयों के बारे में स्पष्ट नहीं है यदि इसके बारे में भी लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पर असर पड़ना निश्चित है क्योंकि, अमेरिका लंबे समय से इस बात पर चिंतित रहा है कि दवाओं की कीमतें उसके घरेलू बाजार में लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी ओर, विदेशों से आयातित दवाएँ सस्ती और प्रतिस्पर्धी होती हैं, जिसे अमेरिकी कंपनियों का दबाव बड़ जाता है। ट्रंप की मंशा, स्थानीय उत्पादन बढ़ाना, रोजगार सृजित करना और अमेरिका को आयात पर निर्भरता से मुक्त करना। इस आदेश में राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है, यह कदम दवाइयों मत्दाताओं को यह संदेश देता है कि ट्रंप अमेरिकी उद्योग और उपभोक्ताओं के हित में कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इसमें रणनीतिक दबावयह है कि चीन, भारत और यूरोप जैसे देशों पर यह अप्रत्यक्ष दबाव है कि वे अमेरिका को केवल उपभोक्ता बाजार की तरह न देखें, बल्कि वहां निवेश करें। इसलिए आज हम मॉडिग्य में उपलब्धजानकारी के संयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, ट्रंप ने भारत पर फोड़ा टैरिफ बम- दवाओं पर 100 पर्सेंट टैरिफ- वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर विश्लेषण।

साथियों बात अगर हम भारत के फार्मा सेक्टर सेक्टर की करें तो, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लिए जाना जाता है। यह इस तरह प्रभावित होगा कि (1) निर्यात पर सीधा असर- अमेरिका की दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 8-9 बिलियन डॉलर की दवाइयाँ निर्यात की थीं। 100 पर्सेंट टैरिफ लगाने से यह व्यापार तुरंत प्रभावित होगा (2) कीमत और

प्रतिस्पर्धा- भारतीय कंपनियों की दवाएं अमेरिकी उपभोक्ताओं को अब दोगुनी कीमत पर मिलेंगी ,जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा कम होगी। (3) निवेश दबाव- भारतीय कंपनियों पर अमेरिका में उत्पादन इकाइयाँ लगाने का दबाव बढ़ेगा। इससे भारतीय दवा कंपनियों को एफडीआई और मर्जर एंड अकिवजीशन के रास्ते तलाशने पड़ सकते हैं। (4) रोजगार पर असर- भारत में लाखों लोग फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हैं। यदि निर्यात घटा तो उत्पादन और रोजगार दोनों पर दबाव पड़ेगा।

साथियों बात अगर हम भारत को जेनेरिक दवाइयों के एंगिल देखें तो यदि जेनेरिक दवाइयों को छूट रहती है तो भारत को ज्यादा असर नहीं छिपाएगा, भारत जेनेरिक दवाइयाँ अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 8.73 अरब डॉलर (करीब 77 हजार करोड़ रूपए) की दवाइयाँ भेजीं, जो भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31 पर्सेंट था। (1) अमेरिका में डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उनमें से हर 10 में से लगभग 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों की बनाई होती हैं। (2) एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में अमेरिका के हेल्थकेयरर सिस्टम के 219 अरब डॉलर बचे थे। 2013 से 2022 के बीच यह बचत 1.3 ट्रिलियन थी। (3) भारत की बड़ी फार्मा कंपनियाँ, जैसे डॉ. रेड्डीज, सन फार्मा, ल्युफिन सिर्फ जेनेरिक दवाएँ ही नहीं बेचती, बल्कि कुछ पेटेंट वाली दवाएँ भी बेचती हैं। वहीं भारत अधिगम निर्यात जेनेरिक दवाइयां का ही करता है।

साथियों बात अगर हम ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाई और जेनेरिक दवाएं में अंतर को समझने की करें तो, ब्रांडेड दवाई- (1) यह वो ओरिजिनल दवाई होती है जिसकी खोज किसी फार्मा कंपनी ने बहुत रिसर्च और भार- भरकम खर्च के बाद की होती



है। (2) इसे बनाने वाली कंपनी को एक तय समय (आमतौर पर 20 साल) के लिए पेटेंट अधिकार मिल जाता है। (3) इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वह दवाई नहीं बना सकती। (4) रिसर्च और डेवलपमेंट पर हुए खर्च को वसूलने के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है।

जेनेरिक दवाई- (1) यह वो दवाई होती है जो ब्रांडेड दवाई का पेटेंट खत्म होने के बाद बाजार में आती है। यह ब्रांडेड दवाई के समान फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। (2) इसका कोई नाम पेटेंट नहीं होता, क्योंकि यह पहले से मौजूद फॉर्मूले की नकल होती है। (3) जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को रिसर्च का खर्च नहीं उठाना पड़ता, इसलिए इसकी कीमत ब्रांडेड दवा के मुकाबले 80 पर्सेंट से 90 पर्सेंट तक कम हो सकती है। अब दो जरूरी बातों को इसमें समझना जरूरी है। (1) ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला ट्रम्प ने क्यों लिया ?-ट्रम्प ने ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका में दवा उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिया है। ट्रम्प का यह कदम उनकी ‘अमेरिका फर्स्ट’ और ‘मेक इन अमेरिका’ नीति का हिस्सा है। ट्रम्प प्रशासन का यह भी मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। (महामारी के दौरान यह बात साफ हुई थी कि अगर सप्लाई चैन टूटती है तो अमेरिका में दवाओं की भारी कमी हो सकती

आर्थिक सहयोग दिया जाए तो वे देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस मामले में सरकार और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रतिभा पलायन रोकने के लिए सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। सरकार को प्रतिभाशाली युवाओं को चिन्हित कर उनकी जरूरतों के अनुसार शोध, स्टार्टअप और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। औद्योगिक समूह रिसर्च और इनोवेशन में निवेश करें जिससे युवाओं को विश्व स्तरीय मंच मिले। कॉर्पोरेट सेक्टर को देश के भीतर ही आकर्षक वेतन और कार्य संस्कृति प्रदान करने का दायित्व उठाना चाहिए।

आज समय ने करवट ली है। प्रकृति भारत को परम वैभव पर देखना चाहती है। इसलिए भारत के सामने अनेक चुनौतियां आ रही हैं। अब समय इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का है। कुल मिलाकर, अमेरिकी कदम भारत के लिए सकारात्मक है। इससे हमें ऐसे कदम उठाने की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपनी प्रतिभा को यहीं रोकें और उन्हें ऐसे अवसर दें जिससे वे विदेश जाने की बजाय देश में ही काम करें। अगर हम अपने युवाओं को यहीं अवसर देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता संभव होगी। मेड इन इंडिया का सपना साकार होगा। अगर सरकार, उद्योग जगत और समाज इस दिशा में मिलकर काम करें तो भारत अपनी प्रतिभा के बल पर न केवल आत्म निर्भर बन सकता है बल्कि दुनिया को नई दिशा भी दे सकता है। तेजी से बदलते विश्व परिदृश्य में हमारे 145 करोड़ नागरिकों वाले देश का हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना अपरिहार्य है।

प्रो. महेश चंद गुप्ता (लेखकविख्यात शिक्षाविद्, चिंतक और वक्ता हैं। वह 44 सालों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं।)

लता जी संगीत की शिखर साध्वी: जयंती नहीं, स्वर-उत्सव है

जिस तरह रज दखारी की तान बन को गहन शांति और आलौकिक अनुभूति में डुबो देती है, उसी तरह लता मंगेशकर का नाम लेते ही रस भरि से गढ़ा, रंग और बर्द की लारसे से संकृत हो उठता है। 28 सितंबर 1929 को इंद्र के एक साक्षात्ग नराटी परिवार में अन्नूी लता जी केवल एक पिटिका बहीं थीं, बल्कि भारतीय संगीत की दस परदेरी थीं, जिन्होंने अपने स्वर से युगों को जोड़ा। उनकी आवाज एक जादूई तार थी, जो रस मानव—प्रेम, विरह, नर्कित, और देशप्रेम को श्राला की गहरायों तक पहुँचाती थी। लता जी का जन्म न केवल एक तारोद्य था, बल्कि भारतीय संस्कृति के एक स्वर्णिम युग का प्रारंभ था, जिसे संगीत को श्राला का दर्शन बना दिया। ‘स्वर कोकिल’ का खिताब उनके लिए केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि उनकी आवाज की पहचान और गहराई का साक्षात्कार था।

अन्का नूत नाम लता थीं, पर उनके पिता, शास्त्रीय संगीतज्ञ और संसर्ग के दिग्गज पीटैट दीनाथ मंगेशकर ने उन्हें ‘लता’ नाम दिया। 1४र में संगीत का ऐसा माहौल था कि मानने हर दीवार से राबिनी और हर ख्या में तानत नूंगता वा। पार्व वर्य की उम्र से ही लता जी ने पिता के नाटकों में अभिनय शुरू किया, और संगीत उनकी नींव का हिस्सा बन गया। लेकिन 1942 में, जब वह मात्र 1३ वर्ष की थीं, उनके पिता का प्रसामयिक निधन ने परिवार को आर्थिक और भवनात्मक संकट में डाला। इस क्शी उम्र में लता जी ने अपने कंघों पर परिवार को त्रिभेदारी उठारें और अपनी आवाज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। यह दुःखी और संकल्प उनकी आवाज में दम कल्या और तीव्रता लाया, जो हर गीत को अमर कर गया।

194४ में नराटी फिल्म ‘कैदी रसाल’ के लिए अन्का पहला गीत (बादु वा नूँ, खेतों सारी कृषि लेस नारी) रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी राह आसान नहीं थी। उस दौर में नूरातों और सनवाद केम जैसी दमदार आवाजों का बोलावला था, और लता जी की कोमल, न्युर आवाज को कई निर्माताओं ने ‘पतली’ करकर दुखरा दिया। लेकिन लता जी का आत्मोत्थरस और अदक परिश्रम ने संगीत की दुनिया को उनकी प्रतिभा का कवत बना दिया। 11949 में फिल्म ‘नल्ल’



डांडिया की धुन में हैं ‘एकता’ का संदेश…!

आज भी डांडिया की धुन में हैं ‘एकता’ का संदेश, गुजरात की सांस्कृतिक परंपरा फैली देश–विदेश। ये नृत्य नहीं सामूहिकता, अनुशासन आनंदोत्सव, ढोल–नगाड़ों के थाप एक लय में होता नृत्योत्सव।

वह दृश्य जब ‘सैकड़ों लोग’ एक साथ करते नृत्य, भारतीय संस्कृति की समृद्धि एवं विविधता दृश्य। डांडिया का महत्व ‘मनोरंजन’ तक नहीं है सीमित, ये समाज को जोड़ने के माध्यम भी है अपरिमित।

भित्ति–भिन्न वर्गों, भाषाओं पृष्ठभूमियों से आते लोग, एक ही ताल पे थिरकते भेद मिटाके करें सहयोग। मजबूत होती एकता की भावना रहती सदभावना, ऐसे आयोजनों का महत्व है प्रगति पथ पर बढ़ना।
संजय एम तराणेकर (कवि, लेखक व समीक्षक)

इस बार हिंदी के बहाने नफरती उचक्कापन

(आलेख : बादल सरोज)

यू भले दस्तावेजों को सबूतों के पहाड़ खड़े किये जाने के बाद भी चुनाव आयोग उन्हें बिना पढ़े और देखे ही निराधार और भ्रामक बता दे, मान्यता प्राप्त राजनीतिक एलनों के सम्प्रमाण जानपनों की भी दाखिल खारिज कर दे, नेता प्रतिपक्ष से भी शपथपत्र पर लिखकर देने को कहें, यू भले ही बिना किसी सबूत के ही जेल में पड़े लोगों की 'जांच जारी है' के नाम पर जमानत देने से इंकार करते-करते पांच सात वर्ष गुजार दें, मगर मामला यदि विग्रह, विभाजन को आगे बढ़ाने वाले, देश में द्वेष फैलाने के उन्के नफरती एजेंडे का हो, तो आनन-फानन में आदेश भी निकल जाता है और उसे फ़ौरन से पेश्वर अमल में लाने का हुकुम भी सुना दिया जाता है।

पिछले सप्ताह ऐसा ही एक कानामा, मोदी सरकार जिसे अपना सबसे महत्वपूर्ण विभाग मानती है, उस सूचना एवं प्रसारण विभाग ने कर दिखाया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी9 भारतवर्ष, आजतक, एबीपी, जी न्यूज़ और टीवी 18 आदि चैनल को औपचारिक नोटिस भेज कर कहा कि उनका चैनल हिंदी का होने के बावजूद उर्दू शब्दों का प्रयोग कर रहा है। उनसे पता नहीं कैसे लेकिन पक्का गिनकर भी बता दिया कि ये चैनल अपनी वर्तनी में 30 फीसद से ज्यादा शब्द उर्दू के इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं कि इसके लिए मंत्रालय ने एक नागरिक की निजी शिकायत को आधार बनाया और इसे तुरंत सुधारने और भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का भी निर्देश दे मारा। बात इतने पर ही नहीं ठहरी — गोयबल्ला का अवतार बन चुके इस मंत्रालय ने चैनलों को पंद्रह दिनों के भीतर शिकायत पर लिए गए निर्णय की सूचना मंत्रालय और शिकायतकर्ता दोनों को देने का आदेश भी दे दिया।

इस पूरे प्रपंच का मजेदार हिस्सा यह है कि उर्दू के उपयोग पर रोक लगाने की बात भी उर्दू के ही एक शेर "उर्दू को हम इक रोज मिटा देंगे जहाँ से / कमबख्त ने वो बात भी उर्दू में कही है" को अमल में लाते हुए ही कही है। इस बारे में चैनल को मंत्रालय

ने जो फ़क़त 7 छोटी पंक्तियों की चिट्ठी लिखी है, उसमें भी तौर, गलत, इस्तेमाल, खिलाफ, शिकायत, कार्यवाही, दिन, तहत जैसे कुल जमा 13 शब्द उर्दू के इस्तेमाल किये हैं, जो पक्के से 30 फीसद से ज्यादा ही होते हैं। मंत्रालय की यह चिट्ठी इसलिए और भी गजब है कि इसमें चैनल के लिए संबोधन अंग्रेजी भाषा में उसकी रोमन लिपि में लिखा गया है।

विडम्बना की बात एक ओर है और वह यह है कि "हिंदी न्यूज़ चैनल द्वारा अपनी रोजाना की टिप्पणियों में अन्य भाषाओं का इस्तेमाल करने को जनता के साथ धोखाधड़ी और अपराधिक कृत्य" बताने वाले येशिकायतीलाल खुद उस महाराष्ट्र के ठाणे में रहते हैं, जहां इन दिनों भाजपा सरकार के राज में हिंदी भाषा बोले भर जाने पर टुकाराई-पिटारि का पुण्यकार्य अंजाम दिया जा रहा है।

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी चैनल के लिए यह नोटिस जनवरी 2025 में केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2025 के तहत दिया है। इन नियमों को बनाने समय दावा किया गया था कि इन्हें इस सेक्टर के आधुनिकीकरण और बेहतर नियंत्रण के लिए बनाया गया है। हालांकि इस देश में टीवी चैनलों पर भाषा और सामग्री के संबंध में कानून और दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद रहे हैं। इन नियमों का घोषित मकसद सामाजिक शालीनता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामुदायिक सद्भाव के मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।

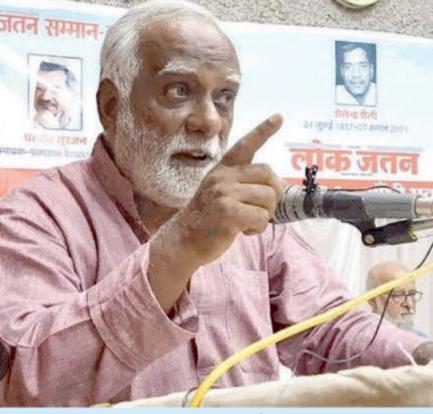
कार्यक्रम संहिता के नाम के ये नियम बाकायदा स्पष्ट करते हैं कि टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली सामग्री में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जो अश्लील, अपमानजनक, या अभद्र हो; जो किसी धर्म या समुदाय पर हमला करती हो; या सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देती हो; जो हिंसा को भड़काती हो या बढ़ावा देती हो; जो जानबूझकर झूठी, भ्रामक या आधी-अधरी सच्चाई बताती हो; जो शिष्टता और अच्छे नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो; जो न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों की गरिमा के विरुद्ध हो। साफ़

हो जाता है कि इनमें से कोई भी नियम हिंदी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती या तमिल के उपयोग करने न करने की बात नहीं करता।

पहली नजर में ही एकदम बेतुकी इस शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए था — मगर बजाय ऐसा करने के, इसे सही मानते हुए इसके आधार पर कदम उठाने और इसका निराकरण करने के आदेश जारी कर दिए गए। यह किसी एक बन्दे जैसी स्वाभिमान के विशेषज्ञ होने वाले अदने अधिकारी द्वारा अज्ञानवश की गयी कार्यवाही नहीं, यह साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की उस अपराधिक प्रक्रिया को तेज कर देने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है; नफरती अभियान पर सरकारी ठप्पा लगाना है।

यह इस धारणा पर आधारित है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। यह सरसर झूठी और भ्रान्त और कुटिल धारणा आर एस एफ के उस कुत्सित अभियान का हिस्सा है, जो भारत की विरासत और बनावट दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, भाषाओं के बारे में जिनका ज्ञान द्वेष और मानस्य से आगे नहीं गया। उनसे निशाने पर सभी भारतीय भाषाएँ हैं, मगर फिलहाल चूँकि उनका मूल मंत्र हिन्दू-मुसलमान के बीच रार और तकरार बढ़ाने का है, इसलिए उर्दू को मुखा बनाया जा रहा है। जबकि सच यह है कि उर्दू टेह हिन्दुस्तानी भाषा है, जो धरती के इसी हिस्से पर जन्मी, पली और हिबदी, देहलीवी, रेख्ता, उर्दू जैसे नामों के साथ जवान हुई।

उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है। पण्डित चन्द्रभान बरहमन उर्दू के पहले कवि हुए हैं। ऐसी अनगिनत मिसालें और भी हैं, मगर चूँकि उन पर पहले भी लिखा जा चुका है, इसलिए उसे दोहराने की बजाय सार में कहें, तो यह कि उर्दू ही हिंदी ही या अथवा किसी भी नाम की कोई भाषा हो, कोई भी भाषा किसी धर्म, संप्रदाय, जाति की नहीं होती। वह कई मतवा इलाकाई होती है। जैसे बांग्ला,



मराठी, गुजराती आदि भाषाएँ हैं, मगर उस तरह हिन्दी-उर्दू नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ-जहाँ हिंदी है, वहाँ-वहाँ उर्दू है और जहाँ-जहाँ उर्दू है, वहाँ उसकी हमजोली हिन्दी है। इसलिए इनके संगम को सदा गंगा-जमुनी कहा और माना गया है। दिलचस्प है कि दोनों का नाभि-नाल संबंध अमीर खुसरो से है और दोनों का पालना बूज और अवधी का रहा है। उसे अल्पसंख्यकों की भाषा बनाकर उसका भावव और आयतन कम करना एक साम्प्रदायिक क्रिमिक की हरकत है। उर्दू सारे धर्म, जातियों की चहेती भाषा है। मूलतः धरती के इस हिस्से पर जन्मी भारत की भाषा है। स्वतंत्रता संग्राम की भाषा है। कौमी तरानों की भाषा है। साम्प्रदायिक एकता, भाईचारे और सद्भाव की भाषा है। हिन्दी ही नहीं, उर्दू सफ़ह के इतिहास में भी उर्दू को कभी अल्पसंख्यकों या मुसलमानों की भाषा नहीं बताया गया और न किसी स्कूल या कालेज में ऐसा पढ़ाया गया। यह खुरफात उन तंग नजरिये वाले षडयंत्रकारियों द्वारा फैलाई गयी अफवाह है, जो इस तरह की भाषाई साम्प्रदायिकता इसलिए भी फैलाते हैं, क्योंकि उर्दू एक सेक्युलर, धर्म और पंथ निरपेक्ष भाषा है। उर्दू तो बहाना है,

असली मकसद मुसलमानों को निशाना बनाकर उन्माद फैलाना है।

उर्दू तो उर्दू, इन फर्जी हिंदी भक्तों को यह भी नहीं पता कि जिस हिंदी के नाम पर वे जालबिखा रहे हैं, वह आधुनिक हिंदी तो बमशुक्ल सवा डेढ़ सौ साल पुरानी है और अंग्रेजी-अंग्रेजी 19वीं सदी में बूजभाषा और अवधी जैसे मजबूत भाषाओं से शब्द भंडार लेकर खड़ी बोली के रूप में अस्तित्व में आई है। इससे पहले, जिसे पुरानी हिंदी कहते हैं वह — अवहट्ट — खुद प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश की अंगुली पकड़कर बड़ी हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दुस्तानी अवाग की विराट एकता से घबराए अंग्रेजों ने फूट डालो आर राज करो की नीति में भाषा को भी इस्तेमाल करने की बुरी नीयत से कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इसे अपनी तरह से ढालने की भीषण कोशिश की; तब जो अंग्रेजों के दास होना सूरभूय की बात मानते रहे, आज सत्ता में पहुँचकर वे उसी राह पर चलने और भाषाओं को भी साम्प्रदायिकता का जरिया बनाने की जी-तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। यह ताजा बहाना उसी कुटिलता को नया जामा पहनाना है।

इन्हें हिंदी चैनल पर अंग्रेजी का बेतहाशा और ज्यादातर अनावश्यक इस्तेमाल किया जाना बुरा नहीं लगता — बहुत मुफकिन है कि रानी एलिजाबेथ और विक्टोरिया के प्रति घनघोर आदर और 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' भाव से उनको लिखी चिट्ठियों के अनुभवों के चलते वे अंग्रेजी को ही अपनी मातृभाषा मानते हों। शायद इसीलिए इन्हें अपने जमानों और खोखली घोषणाओं के लिए इस भाषा के जिंगल्स और पञ्चलाइन्स ही अधिक भाती हैं, मगर इस देश की जमीन पर जन्मी और संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्ज उर्दू के शब्दों का उपयोग इन्हें 'जनता के साथ धोखाधड़ी और अपराधिक कृत्य' लगता है।

जोरदार बात यह है कि अन्यायी बुराई की गौरवशाली विरासत की बहाली करने की दुहाई देने

लदाख के जेन-जेड क्रांति को यदि समय रहते ही नहीं कुचला तो

कमलेश पांडेय

केंद्र शासित प्रदेश लदाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जारी आंदोलन ने गत्व बुधवार को हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। इसके बाद लेह में प्रदर्शनकारी छात्रों की सुरक्षाबलों से झड़प हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 70 से ज्यादा घायल हैं। वहीं, प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई। चूँकि यह अतिवादी कार्रवाई है, इसलिए हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं, हालात को देखते हुए लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। बिना मंजूरी के रैली और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है।

बताते चलें कि लदाख को राज्य का दर्जा समेत कई मांगों पर सोशल ऐक्टिविस्ट सोमन वांगचुक विगत 15 दिनों से भूख हड़ताल में हैं। लिहाजा, उनकी मांगें पूरी न होने पर प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को बंद बुलाया। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर लोगों से लेह हिल कार्डसिल पहुंचने की अपील की गई। जिसके बाद वद बुधवार को सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे। इसी दौरान हिंसा हुई। सरकारी सूत्रों ने कहा कि हिंसा में राजनीति से प्रेरित साजिश की बूआ रही है। वहीं, केंद्र सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सोमन वांगचुक के उकसाऊ बयानों से यह हिंसा भड़की है। इससे पहले वांगचुक ने हिंसा पर दुख जताते हुए अनशन तोड़ दिया। उन्होंने इन घटनाओं के लिए जेन-जेड (1997 से 2012) के बीच जनस लेने वाली पीढ़ी) की हताशा को जिम्मेदार ठहराया और शांति की अपील की। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनकारियों की 4 अहम मांगें हैं— लदाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्वोत्तर की तरह संघीयतात्मक सुरक्षा, करगिल, लेह की अलग-अलग लोकसास सीट और सरकारी जाँब्स में में स्थानीय लोगों को भर्ती। इससे स्पष्ट है कि लोकसास में नेता प्रतिपक्ष और चीन के हमदर्द राहुल गाँधी भी सोशल-बंगलादेश की तरह पूरी देश में यही कुछ चाहते थे, के मनोरथ पूर्ण होने की तरफ बात बढ़ चली है। यदि शेष भारत में गृहयुद्ध भड़कता है तो इसके लिए इस

देश में केवल विपक्षी दल, कथित सिविल सोसायटी और बाहरी शक्तियाँ, यथा- अमेरिकी डीप स्टेट तथा इस्लामिक अतिवादी संस्थाएँ दोषी तो होंगी ही, साथ ही साथ इस बंद से बदतर स्थिति के लिए कथित राष्ट्रभक्त हिंदू और सनातन धर्म प्रेमी लोगों का एक बड़ा तबका भी होगा जो उनके इशारे पर थिरकते हैं।

ऐसा इसलिए कि आप लदाख की इस घटना से लेकर नेपाल के हाल-फिलहाल के वाक्ये तक इनके द्वारा लिखी व बोली गई अनाप-शानाप बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। वास्तव में ये जाने-अनजाने में देश धर्मविरोधी तत्वों के हथियार बन रहे हैं। यह गम्भीर बात है। इससे संवैधानिक सफलता भी संदिग्ध हुई है। सच कहूँ तो भारत के अतिसंवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश 'लदाख' से जेन-जेड क्रांति का जो आगाज दिखाई-सुनाई पड़ा है, यह हमें समय रहते ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। चाहे सम्बन्धित सेना हो या सिविल व पुलिस प्रशासन, यदि उनके द्वारा अमेरिकी खुफिया इकाई सीआईए द्वारा प्रोत्साहित इस कथित जेड-जेन क्रांति को सख्ती पूर्वक नहीं कुचला गया तो उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा!

बेहतर होगा कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों को अविलंब कैद करके उन्हें आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उनके कुकर्मों से धन-जन की हानि हुई है, अन्याय भारतीय लोकतंत्र में भी एक लत टूट स्थापित हो जाएगा। एशियाई लोकतंत्र की सफलता पर सवाल उठेंगे। ऐसा इसलिए कि पश्चिमी लोकतंत्र खूनी लोकतंत्र है, यथप्राती डेमोक्रेसी है। जिसका मकसद दुनिया भर में लोकतांत्रिक जनभावना मजबूत करना नहीं, बल्कि अपने आर्थिक व साम्राज्यवादी लाभ के लिए दुनिया में कठपुतली सरकार कायम करना है।

यही वजह है कि जेन-जेड जैसी कथित क्रांति से हार ले सता परिवर्तन और बन रही कठपुतली सरकारों को दुनियावी लोकतंत्रों की सफलता के लिहाज से उचित नहीं समझा जा सकता है। इसलिए लदाख घटनाक्रम के बाद भारत को ठोस

और प्रभावी कदम उठाने ही होंगे और इससे अपने पड़ोस को भी लाभान्वित करने की सद्भावना रखनी होगी।

कहना न होगा कि 2014 की सनातन युवा क्रांति के बाद बनी भाजपा नीत मोदी सरकार की सफलता से ही भारत, अमेरिका-चीन और अरब देशों के निशाने पर है। इसलिए श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल आदि में जो जेन-जेड क्रांति हुई, उसका मकसद भारतीय राजनेताओं और सेना के धैर्य की परीक्षा लेना था। जब हम लोकतंत्र की पैरोकारी में मजबूती पूर्वक विश्वास रखते हैं तो लदाख जेन-जेड क्रांति हमें मुबारक कर दिया गया।

सवाल है कि यह भी प्रयोग केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर के बजाय बौद्ध धर्म बहुल लदाख में करवाया गया ताकि बौद्धों के प्रति हिंदुओं के मन में नफरत पैदा हो और चीन-भारत व तिब्बत-भारत के रिश्तों में परलीता लगे। इसलिए अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ होता तो बेहतर होता। लेकिन चरमपंथियों और हिंसकों को कुचलने के बजाय स्थानीय सेना व प्रशासन द्वारा ऐसे अराजक तत्वों से बात करने से समकालीन लोकतंत्र के प्रति गलत संदेश गया है।

लिहाजा, अविलंब इसकी भरपाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, रूस और चीन आदि के साथ मिलकर अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्याय असहयोग मिलने पर भारत की सेना को ही इन पर आक्रमण करके इन्हें भारतीय भूभाग में मिला लेना चाहिए। इसके साथ ही पश्चिमी देशों व ब्रिक्स देशों जैसे लोकतंत्र के कथित दरिदों को ग्लोबल साउथ के समक्ष बेनकाब करने की स्पष्ट रणनीति अख्तियार करनी चाहिए। कठने का तातपर्य यह कि विधि के शासन को बहाल करने के लिए भारत व उसके पड़ोसी देशों से बातें को आपसी सांठगांठ करके व स्थानीय सिविल व पुलिस प्रशासन को भारोसे में लेकर निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। इस दिशा में हर तरह की कुर्बानी के लिए भी तैयार रहना चाहिए और

किसी तरह के 'कल्लेआम' से पुरेज नहीं करना चाहिए। अन्याय भारत विकास और सुशासन की रैस में पिछड़ जाएगा।

समकालीन जेन-जेड की हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए लोगों को आशंका है कि जी-7 और ब्रिक्स के कतिपय चतुर सुजान देश यही अराजकता चाहते हैं, ताकि उनके गोला-बारूद की खपत बढ़े। इसी की आड़ लेकर वे दुनियावी प्राकृतिक संसाधनों को लूट सकें। इसलिए भारत को अविलंब जिला स्तर पर अपनी तैयारी को धार दी जानी चाहिए, ताकि हिंसक व अराजक तत्वों को उनकी आँकल में रखा जा सके। अन्याय यह 'खूनी लोकतंत्र' भविष्य में अमेरिकी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। बहरहाल ये अराजकता पैदा करके हथियार बेचेगे और भारतीय उपमहाद्वीप भी अरब व खाड़ी देशों की तरह झुलसता रहेगा।

बताते चलें कि कथित पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लदाख में चल रहा प्रदर्शन जिस प्रकार से हिंसक हो गया और भाजपा के कार्यालय तक को निशाना बनाया गया, उसमें भाड़े के उल्पाती शामिल नहीं हैं तो क्या हैं? यह ठीक है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोमन वांगचुक की अनुप्राई में लंबे वक्त से यह मांग उठाया ही है और इसे लेकर केंद्र से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन, इस दौरान इस सोच का हिंसा का हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण और स्थितजनक दोनों है और उनके खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पूरे देश में एक सही संदेश जाए।

यह ठीक है कि सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35-ए के प्रावधान हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर से अलग कर लदाख को केंद्र शासित राज्य बनाया था। तब सरकार ने वादा किया था कि हालात सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 6 साल बाद लोगों का भरोसा और स्रड डामनागना है लगे है। फिर भी लेह में हिंसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे विशिष्ट ताकतों के हाथ की पड़ताल और जम्मू-कश्मीर सरकार की परोक्ष भूमिका की जाँच होनी चाहिए।



ग़ैड ऐक्सोटिका सोसायटी इन्दौर में नवरात्र महोत्सव के तहत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व गरबे की प्रस्तुति दी जा रही है। इसमें छोटे छोटे बच्चों की ड्रेस व उनकी प्रस्तुति सभी को लुभा रही है।

28 सितंबर 2025 अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर

बेटी है तो कल है। स्वतंत्र लेखक हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

बेटियाँ हर एक परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। क्योंकि हम सनातन संस्कृति वाले ऐसे पूजनीय मानते हैं वह दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। इसलिए कन्या हमारे समाज को आपस में एकता के सूत्र में बंधे रखती हैं। जिसमें परिवार में स्नेह व वात्सल्य भाव बना रहता है, जब बहन बेटियाँ घर में रहती हैं। हम सभी को इन शक्ति स्वरूपा बेटियों के भविष्य को प्रगति पंथ पर आगे बढ़ने हेतु आगे आना ही होगा। बेटी है तो कल है यह सिर्फ चार लाइन नहीं हैं। यहाँ भविष्य में नारीशक्ति को आगे बढ़ाने हेतु मान सम्मान है। हमेशा बेटियाँ में समाजिक दुष्ठीकोष व समन्वय बना रहना चाहिए। वह एकजुटता का संचालन करती हैं, और हमेशा से सेवाभावी समझदार व परोपकारी तो रहती हैं, उसी के साथ साथ वह अपने माता-पिता के लिए भी हर समय दुःख-सुख में सबसे आगे खड़े रहने वाली बेटियाँ ही होती हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा की बेटा अंश ही तो बेटी वंश है। आज समाजिक स्तर पर वह अपने आप को आधुनिक जमाने में आगे बढ़ा रही हैं। हम देखें तो वह साहसी व निडर होकर पुरुष-प्रधान समाज में उनकी एक अलग जगह बना रही है। यहाँ बहुत गर्व की बात है। शादी के बाद वह दो परिवारों को

साथ में लेकर चलने वाली बड़े सौभाग्य से मिलती है बेटियाँ। संस्कारों की दहलीज पर सोपरी जब आजादी के साथ शिक्षा व संस्कारों को लेकर समाजिक बदलाव को राष्ट्र व समाज के साथ लिए वह कन्या देवी स्वरूपा अपने शुभ कदमों का अब पर्दापण कर रही हैं। क्योंकि समाज में यह वैचारिक भावना जाना चाहिए कि बेटियाँ बोज़ नहीं होती हैं, वह तो संस्कारों की परिधि में रहकर भी दो परिवारों का आत्मविश्वास बढ़ती है, बेटी है तो कल है। मनुष्य जीवन में नर व नारायणी दोनों जरूरी हैं। तभी सम्पूर्ण धरती पूर्ण होती है। इस लिए बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दिया जाये। क्योंकि वे बेटों को सूर्य सा ओजस्वी मानते हैं, पर बेटों को देते हैं जगन्म की संज्ञा, पर वह भूल जाते हैं कि अंधेरे में जगन्म ही चमकते हैं। इसलिए बेटी है तो कल है। बालिका दिवस का यहाँ संजोग की इस बार नवरात्रि पर्व भी चल रहा है जिसमें हम सनातनी लोग कन्या को देवी के रूप में पूजते हैं। सपत्नी अष्टमी व नवमी पर घर घर में छोटी-छोटी बच्चियों को हल्दी कुंकुम वह चुनरी भेंट करके पुजते हैं। तो फिर उनके प्रति हमारे मन में नाकारात्मक विचार क्यों आते हैं। हमें बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सयोग करना होगा। क्योंकि बेटी है तो कल है और यहाँ बेटियाँ ही भारत का भविष्य है। इन्हें खुलें आसमान में उड़ने दो।

ट्रंप का टैरिफ बम: वैश्विक फार्मा पर मंडराता संकट

जैसे ही वैश्विक बाजारों में सूर्योदय की पहली किरणें चमकी, वॉल स्ट्रीट का ट्रेंडिंग प्लोर भूकंप की तरह कांप उठा। शेयरों की चौखे, लुढ़कते इंडेक्स और अफरा-तफरी के बीच एक नाम तूफान की तरह गूँज रहा था— डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति की आधी रात की घोषणा ने न केवल फार्मास्यूटिकल जगत को धराशायी कर दिया, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक कड़वी सच्चाई की चोटी पर ला खड़ा किया। कल्पना कीजिए, वह दवा-दुनिया जहाँ सस्ते दवाओं पर लाखों जिंदगियाँ टिकी हैं, अचानक महंगाई के काले बादलों में लिपट जाती है। यह कोई मामूली नीति नहीं, बल्कि 'अमेरिका फर्स्ट' का एक खतरनाक दांव है, जो अमेरिकी हितों को मजबूत करने के बजाये वैश्विक सप्लाई चेन को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है। और भारत? 'विश्व की फार्मसेस' के रूप में जाना जाने वाला यह फार्मा महासागर अब तूफान के सिरे पर खड़ा है। लेकिन क्या यह विनाश का अंतिम संकेत है, या फिर अवसरों की नई सुबह?

ट्रंप का यह तिर 'अमेरिका फर्स्ट' मंत्र को एक घातक आयाम देता है। 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड डी और पेटेंटेड दवाओं पर 100

प्रतिशत टैरिफ का ऐलान न केवल घरेलू उत्पादन को पंख लगाने का प्रयास है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ढाल बन जाता है। महामारी की वे काली रातें अभी आंखों में तमाही हैं, जब सप्लाई चेन की डोर टूटने से दवाओं की भुखमरी ने दुनिया को थरो दिया था। ट्रंप प्रशासन का तर्क अटल है: विदेशी निरभरता एक जहर की घंटी है। कंपनियाँ अगर कर दिया, बल्कि पूर्ण निरभरता ही है, बल्कि ही निर्माण को शुरू हो गया हो, तो टैरिफ से सूट मिलेगी। यह प्रलोभन निवेश को ललचाता तो है, लेकिन वास्तव में वैश्विक व्यापार को एक अग्निशित भंवर में धकेल रहा है। यूरोपीय संघ जैसे सहयोगियों पर पहले से 15 प्रतिशत की सीमा शिकंजा कस चुकी है, लेकिन यह नया बोज़ उनके निर्यात को खून बहा सकता है। सिव्स और जर्मन दवा दिग्गजों—लोजा, नोवार्टिस और रोग के शेरों में—1-2 प्रतिशत की गिरावट इसका जीता-जागता प्रमाण है, जबकि एशियाई बाजारों में चुगई और सुमितोमो फार्मा जैसे नामों को 5 प्रतिशत तक का धक्का लगा।

भारत, वैश्विक चेसबोर्ड का केंद्रीय मोहरा, अपने फार्मा उद्योग के दम पर 'विश्व की फार्मसेस' है। 2024 में अमेरिका को 8.7

अरब डॉलर का जेनेरिक दवा निर्यात, जो 2025 में 10.5 अरब डॉलर तक पहुंचा। अमेरिकी प्रिस्क्रिप्शन का 40% भारतीय जेनेरिक्स पर निर्भर। ट्रंप की ब्रांडेड दवाओं पर नीति से जेनेरिक्स को तत्काल खतरा कम, क्योंकि ये 80-90% सस्ती हैं। फिर भी, 'ब्रांडेड जेनेरिक्स' को ब्रांडेड श्रेणी में शामिल करने से डॉ. रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूफिन (30-47% अमेरिकी राजस्व) को नुकसान हो सकता है। बाजार में हलचल—सन फार्मा 3-5% और फार्मा इंडेक्स 2.4% गिरा। लेकिन भारत के लिए यह संकट नहीं, अवसर है। कम लागत मॉडल और अमेरिकी प्लांट्स में निवेश (सन फार्मा, बायोर्बॉन) से भारतीय कंपनियाँ तूफान पार कर सकती हैं। यह नीति अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाती है, जबकि भारत नई रणनीतियों से चमकेगा।

जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं का अंतर समझना जरूरी है। ब्रांडेड दवाएँ मूल खोज होती हैं, जिन पर सालों की रिसर्च और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। पेटेंट के 20 साल तक की कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए कीमते बहुत अधिक रहती हैं। दूसरी ओर, जेनेरिक दवाएँ पेटेंट खत्म होने के बाद बनती हैं—वही

फॉर्मूला, लेकिन बिना रिसर्च खर्च के, जिससे ये 80-90% सस्ती होती हैं। भारत का दम यहीं है: कम लागत, उच्च गुणवत्ता। 2013 से 2022 तक अमेरिकी हेल्थकेयर ने भारतीय जेनेरिक्स से 1.3 ट्रिलियन डॉलर बचाए। लेकिन अगर टैरिफ जेनेरिक दवाओं तक पहुंचा, तो अमेरिकी मरीजों की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा। गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि दवाएँ दोगुनी महंगी हो सकती हैं। ट्रंप का दावा है कि लंबे समय में स्थानीय उत्पादन से फायदा होगा, लेकिन अल्पकालिक नुकसान तय है।

यह टैरिफ सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं। ट्रंप ने किचन कैबिनेट्स, बाइक्सम वैनिटी और अपहोल्स्टेड फर्नीचर पर क्रमशः 50% और 30% टैरिफ लगाया है। इससे आयातित सामान महंगा होगा, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और बिल्डर्स पर दबाव बढ़ेगा। राष्ट्रीय होम बिल्डर्स एसोसिएशन के मुताबिक, निर्माण लागत पहले ही 30% बढ़ चुकी है। यह कदम अमेरिकी फर्नीचर उद्योग को बचाने के लिए है।

कोशिश है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को झटका देगा। नियतनाम, चीन और मैक्सिको जैसे देशों से निर्यात प्रभावित होगा,

और अमेरिका महंगा बाजार बनेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन, जो अमेरिकी दवा आयात का 60% हिस्सा आपूर्ति करता है, पहले से ही 15% टैरिफ का बोझ सह रहा है। अब 100% टैरिफ का खतरा यूरोपीय ब्रांडेड दवाओं के निर्यात को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ट्रंप का चीन के साथ पुराना टकराव नया संकट पैदा करेगा, जहाँ फार्मा सप्लाई चेन पहले ही दबाव में है। विकासशील देशों के लिए यह चुनौती और गंभीर है: सस्ती दवाओं तक पहुंच सीमित होगी, क्योंकि वैश्विक कीमते आसमान छू रही हैं। अमेरिकी दवा लागत में सालाना 51 अरब डॉलर की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, अमेरिका में नई फैक्ट्रीयों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन अल्पकालिक मुद्रास्फीति और आपूर्ति बाधाएँ वैश्विक विकास दर को 0.5-1% तक कम कर सकती हैं।

भारत के लिए यह दोधारी तलवार है। चुनौती गंभीर है, निर्यात में कमी से लाखों नौकरियाँ दांव पर हैं। फिर भी, अवसर भी उजगर हैं। यूरोप, अफ्रीका और लैटिन

अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में भारत को अपनी पैठ बढ़ानी होगी। 'मेक इन इंडिया' को 'मेक इन अमेरिका' से जोड़कर द्विपक्षीय समझौतों का सहारा ले सकते हैं। सन फार्मा और डॉ. रेड्डीज जैसी कंपनियाँ पहले से ही अमेरिका में अरबों रुपये का निवेश कर रही हैं। भारत को अपनी सटीक कूटनीति के दम पर चीन का भारोसेमंद विकल्प बनना होगा। भविष्य में जेनेरिक दवाओं से आगे बढ़कर ब्रांडेड और बायोसिमिलर दवाओं में नवाचार उद्योगपतियों को लाभ और श्रमिकों को रोजगार का आकर्षक वादा। मगर यह कदम वैश्विक कूटनीति में गहरी दराप पैदा कर सकता है। भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी हाल के वर्षों में सशक्त हुई है, लेकिन व्यापारिक तनाव इसे कमजोर करने का खतरा लाता है। फिर भी, भारत के पास

सुनहरा अवसर है: चीन के मुकाबले खुद को विश्वसनीय और सुदृढ़ विकल्प के रूप में स्थापित करने का। वैश्विक स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह नीति संशोधन को करा रा झटका देगी, क्योंकि दवाएँ सीमाओं से परे मानवता की साक्षात् जरूरत हैं।

ट्रंप का यह टैरिफ बम वैश्विक आर्थिक संतुलन को उथल-पुथल में डाल रहा है। अमेरिका का संदेश बिल्कुल साफ है: "हमारा हित सर्वोपरि।" भारत के सामने चुनौती विकट है, मगर रणनीतिक सूझबूझ इसे सुनहरे अवसर में बदल सकती है। वैश्विक व्यापार एक जटिल ताना-बाना है—एक धागा टूटने से पूरी व्यवस्था डामना सकती है। इतिहास गवाह है कि संकट ही नई ताकतों को जन्म देते हैं। भारत का फार्मा उद्योग, अपनी अदम्य लचीलता और नवाचार की शक्ति के बल पर, इस तूफान को न केवल झेल सकता है, बल्कि पहले से कहीं अधिक सशक्त होकर उभर सकता है। सवाल यह है: क्या विश्व इस दांव को स्वीकार करेगा, या नई साझेदारियों के साथ करा रा जवाब देगा? समय इसका खुलासा करेगा, लेकिन यह शुरुआत निश्चित रूप से विस्फोटक है।

तीन राज्यों में कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन जोरदार , झारखंड में ट्रैक पर उतरे लाखों

सितंबर 2025 में आयोजित व्याख्यानमाला के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि आज महिलाओं की भागीदारी समाज और राष्ट्र निर्माण में पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि स्त्री-शक्ति केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी उसकी बराबरी की भूमिका होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि स्मार्टशक्ति के बिना राष्ट्र अधूरा है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि भारतीय संस्कृति में नारी को सदा पूजनीय और निर्णायक स्थान दिया गया है, इसलिए संघ परिवार की शाखाओं और गतिविधियों में महिलाओं का सक्रिय योगदान भविष्य की दिशा तय करेगा।

-- डॉ.प्रियंका सौरभ

भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में स्थापित है। 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित यह संस्था मूलतः पुरुष swamyamsevak के लिए बनी थी। इसकी शाखाओं, अनुशासन और विचारधारा ने धीरे-धीरे भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा असर डाला। परन्तु जब यह महिलाओं की भूमिका को और देखते हैं, तो तस्वीर कुछ अलग मिलती है। आरएसएस के समानान्तर 1936 में जन्मी "राष्ट्र सेविका समिति" ने ही स्त्रियों के लिए रास्ता खोला। आज जब संघ अपनी शताब्दी मना रहा है, तब इस यात्रा पर नजर डालना जरूरी है कि स्त्रियों की

भागीदारी कहीं से शुरू हुई और 2025 तक वह किस मुकाम तक पहुंची।

शुरुआती दौर: 1925 से 1936

संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई। यह संगठन अनुशासन, परेड, शाखा और राष्ट्रवाद पर आधारित था। लेकिन इसकी संरचना पुरुष प्रधान रही। हेडगेवार स्वयं मानते थे कि स्त्रियों को अलग मंच चाहिए, क्योंकि उस समय के सामाजिक परिवेश में स्त्रियों का सीधे पुरुष शाखाओं में आना सहज नहीं माना जाता था। इसी पृष्ठभूमि में 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर ने विजयादशमी के दिन वर्धा में "राष्ट्रसेविका समिति" की स्थापना की। हेडगेवार ने भी इस पहल का स्वागत किया और सुझाव दिया कि महिलाएँ अपनी संस्था चलाएँ, ताकि वे अपनी शक्ति, संस्कृति और नेतृत्व को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकें। इस तरह महिलाओं की भागीदारी औपचारिक रूप से शुरू हुई।

सेविका समिति की स्थापना और शुरुआती संघर्ष

1939 में पहली बार समिति ने प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया। धीरे-धीरे अलग-अलग प्रांतों में इसकी शाखाएँ बनने लगीं। समिति का उद्देश्य केवल राष्ट्रवादी विचार फैलाना नहीं था, बल्कि स्त्रियों में 'मातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्व' (मातृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व) जैसे गुणों का विकास करना भी था। इसमें शारीरिक प्रशिक्षण, योग, गीत, खेल, अनुशासन और समाजसेवा शामिल किए गए। आजादी के आंदोलन में भी समिति की महिलाओं ने परोक्ष रूप से भूमिका निभाई। परन्तु उनकी गतिविधियाँ मुख्यतः सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों तक सीमित रही।

1940 से 1970 का दशक: विस्तार की ओर

स्वतंत्रता के बाद के दशकों में समिति का नेटवर्क



बढ़ा। लक्ष्मीबाई केलकर की मृत्यु (1978) तक संगठन कई राज्यों में फैल चुका था। उनके बाद सरस्वती आपटे प्रमुख संचालिका बनीं। इस समय तक शाखाओं की संख्या हजारों में पहुँच गई थी। समिति का जोर महिला शिक्षा, संस्कार, और सेवा परियोजनाओं पर रहा। आपातकाल (1975-77) में समिति से जुड़ी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शनों में भी भाग लिया। इस दौर ने उन्हें राजनीतिक रूप से अधिक सचेत और सक्रिय बनाया।

1980-2000: आधुनिकता और परम्परा का संघर्ष

90 के दशक में जब भारतीय राजनीति में भाजपा और संघ परिवार का प्रभाव बढ़ने लगा, तो महिलाओं की भागीदारी भी चर्चा में आने लगी। समिति ने इस समय शहरी और पेशेवर महिलाओं तक पहुँच बनाने की कोशिश की। महिला शिक्षाकर्मी, चिकित्सक और नौकरीपेशा स्त्रियाँ समिति के कार्यक्रमों से जुड़ने लगीं। 1994 में उपाताई चाटे और 2006 में प्रमिलाताई मेहे प्रखर नेतृत्व के रूप में सामने आईं। इन नेताओं ने महिला शाखाओं को आधुनिक मुद्दों—जैसे कामकाजी महिलाओं की चुनौतियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार में संतुलन—से जोड़ा।

2012 से आगे: शांथक्का का नेतृत्व

2012 में वैदकामा शांता कुमारी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से "शांथक्का" कहा जाता है, राष्ट्रसेविका समिति की प्रमुख संचालिका बनीं। उनका जन्म 1952 में हुआ और वे लंबे समय से संघ परिवार के कार्य में सक्रिय थीं। उनके नेतृत्व में समिति ने अपना विस्तार और तेज किया। आज समिति के पास चार से पाँच हजार शाखाएँ हैं, जो लगभग 800 से अधिक जिलों में फैली हुई हैं। यद्यपि सटीक आँकड़े संगठन सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन अनुमान है कि लाखों महिलाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ी हुई हैं। समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, छात्रावास और महिला सशक्तिकरण परियोजनाएँ चला रही है। शहरी महानगरों में भी इसकी शाखाएँ सक्रिय हो रही हैं।

संघ और महिला प्रश्न

संघ के भीतर महिलाओं को औपचारिक सदस्यता या नेतृत्व स्थान नहीं दिया गया है। आरएसएस की शाखाएँ केवल पुरुषों के लिए ही हैं। महिलाएँ केवल समिति के माध्यम से संघ के विचारधारा संसार का हिस्सा बनती हैं। आलोचकों का कहना है कि यह व्यवस्था महिलाओं को मुख्यधारा से बाहर रखती है। वे पुरुषों के बराबर निर्णायक पदों पर नहीं पहुँच पातीं।

परन्तु समर्थकों का मत है कि अलग संगठन होने से महिलाएँ स्वतंत्र रूप से नेतृत्व और गतिविधियाँ विकसित कर पाती हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार कहा है कि महिलाओं की भागीदारी "प्रकृतिक रूप से" बढ़ रही है। परन्तु अब भी नेतृत्व संरचना में असमानता साफ़ दिखाई देती है।

वर्तमान स्थिति (2025)

संघ अपनी शताब्दी मना रहा है। उसके लगभग 83,000 शाखाएँ देशभर में सक्रिय बताई जाती हैं। वहीं राष्ट्रसेविका समिति की शाखाएँ भी लगातार बढ़ रही हैं। समिति अब गाँवों के साथ-साथ महानगरों में भी काम कर रही है। इसके प्रशिक्षण वर्गों में स्कूली छात्राओं से लेकर पेशेवर महिलाएँ तक भाग ले रही हैं। 2025 में समिति का चेहरा परम्परा और आधुनिकता का मिश्रण है—जहाँ एक ओर मातृत्व और परिवार आधारित मूल्य हैं, वहीं दूसरी ओर समाज सेवा और महिला नेतृत्व के अवसर भी हैं। समिति ने लाखों महिलाओं को संगठित कर आत्मविश्वास और सामूहिकता दी। शिक्षा, सेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समाज पर ठोस असर पड़ा। महिलाओं को नेतृत्व और प्रबंधन का अवसर मिला। महिलाएँ संघ की मुख्य धारा (आरएसएस) में निर्णायक भूमिकाओं से बाहर नहीं। संगठन का वैचारिक ढाँचा महिलाओं को परम्परागत भूमिकाओं तक सीमित करता है। आधुनिक नारीवादी विमर्श से समिति का दृष्टिकोण टकराता है, क्योंकि वह स्वतंत्रता और समानता की बजाय मातृत्व और संस्कृति पर जोर देती है।

सितंबर 2025 में आयोजित व्याख्यानमाला के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि आज महिलाओं की भागीदारी समाज और राष्ट्र निर्माण में

पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। व्याख्यानमाला में यह भी कहा गया कि 2025 का भारत उस मुकाम पर खड़ा है, जहाँ महिला नेतृत्व केवल शूरकर नहीं बल्कि र्निर्णायक भूमिका निभा रहा है। वक्तों ने यह भी जोड़ा कि आधुनिक शिक्षा, तकनीक और आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में महिलाएँ जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, संघ परिवार को भी उसी अनुरूप अपनी संरचना और कार्यप्रणाली को और खुला बनाना होगा। व्याख्यानमाला में अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और विचारकों ने भी महिला नेतृत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रसेविका समिति की महिलाएँ दशकों से शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में काम कर रही हैं। यह तर्क दिया गया कि यदि 1925 में संघ की नींव रखी गई थी, तो उसी दशक में महिलाओं के लिए समानांतर संगठन की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं की उपस्थिति को शुरुआत से ही महत्वपूर्ण माना गया।

1925 से 2025 को यात्रा दिखाती है कि संघ की विचारधारा से प्रेरित महिलाओं ने अपना अलग संगठन खड़ा कर लिया और उसे राष्ट्रीय स्तर तक फैलाया। लक्ष्मीबाई केलकर से लेकर शांथक्का तक यह सिलसिला निरंतर चला है। आज जब भारतीय समाज में महिलाएँ राजनीति, शिक्षा, व्यवसाय और सेना तक में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, तब यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि—क्या भविष्य में महिलाएँ सीधे संघ की शाखाओं और नेतृत्व में भी शामिल होंगी, या वे हमेशा समानान्तर संगठन तक ही सीमित रहेंगी? संघ की शताब्दी महिलाओं की इस यात्रा का पड़ाव भी है—एक यात्रा जिसमें परम्परा, अनुशासन, सेवा और नेतृत्व का संगम है, लेकिन समानता और सहभागिता की चुनौती अब भी शेष है।

मतदान में धांधली के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त

मनोरंजन सासमल, बरिध पत्रकार

भुवनेश्वर :- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निदेश पर, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भक्त चरण दास के आह्वान पर, भाजपा सरकार द्वारा की गई मतदान में धांधली के विरोध में, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जिला, ब्लॉक, एनएसी, नगर पालिका और पंचायत स्तर पर लोगों से इस सरकार के विरोध स्वरूप हस्ताक्षर एकत्र किए जाएँगे। इसके लिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दास ने प्रत्येक जिले के लिए निम्नानुसार पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निदेश दिया है कि यह कार्यक्रम 12 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाए।

पर्यवेक्षक शीघ्र ही जिला समन्वयकों से संपर्क कर अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे और जनजागरण करेंगे तथा पंचायत स्तर से लेकर जिले तक हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाकर एकत्रित हस्ताक्षरों की सूची 12 अक्टूबर तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जमा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस विज्ञापित में कहा कि उक्त सूचियाँ शीघ्र ही



अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय को भेज दी जाएँगी। इस संदर्भ में, श्री रवि मल्लिक और संतोष भोला अंगुल जिले के पर्यवेक्षक हैं, जबकि बालासोर- देवेंद्र मोहंती और हलधर सेठी, बारगढ़- देवसिमा सापल, सत्य नारायण साहू, भद्रक- बिजन नायक, हिमांशु लेंका और एसके मसूद अल्लू, भुवनेश्वर- सुजीत पाधी, अमृता

दास, बल्लंगीर- बलभद्र माझी, उत्सव साहू, फकीर जगत, बौध- रंजीत दाश, अकबर खान, कटक- मानस रंजन आचार्य, श्रीनिवास रौत्रया, कटक शहर- देवेंद्र साहू, दुर्योधन बेहरा, देवगढ़- जयंत कुमार साहू, सुजत प्रधान, ढेंकनाल- चिन्मय सुंदर दास, सारदा प्रसाद प्रधान, गंजम पूर्व- जैकब प्रधान, जितेंद्र प्रधान, गंजम पश्चिम- प्रदीप स्वेन, गजपति-

अमिया पटनायक, वोकाली सेठी, जगतसिंहपुर- बंदिता परिदा, अकब खान, जाजपुर- बनकानिधि बेहरा, मिलन पटनायक, झारसुगुड़ा- सस्मिता पांडा, धर्मेश मिश्रा, कालाहांडी- प्रशांत बिशोई, संजय मंडल, केद्रपाड़ा- अभिलाष मनिषा, राजकिशोर बारिक, क्योंझर- प्रहलाद पूर्ति, योगेश अग्रवाल, खोर्धा- तरुण कौंत मिश्रा, मोहन हेम्वम, देबाशीष महापात्र, कोरापुट- भरत बेमल, अखिल भात्रा, मयूरभंज पूर्व- यशोवंत सिंह लागुरी, नलिनोमोहंती, मयूरभंज पश्चिम- सुदर्शन जेना, निरोज लोचन दास, मलकानगिरी, लिपिका माझी, बालुकेश्वर नायक, नबरंगपुर- निमाई सरकार, सीमांचल गिरि उल्लाका, नुआपाड़ा- द्रेपदी माझी, मुरलीधर नायक, नयागढ़-श्वेतविक पटनायक, निशिकांत मिश्रा, पुरी-शुभेंद्र मोहंती, विनोद पटनायक, रायगढ़- राजाबल माझी, कृष्ण चंद्र कुमिलदीप, राउरकेला-रमेश केरकेटा, अमित बिस्वाल, संबलपुर-वीरन पटनायक, शांतनु साहू, सुबरनापुर-मोतीलाल दास, कमल चंद्र तांडी, नागेंद्र प्रधान, अनंत सायन पाढ़ी को सुंदरगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रधानमंत्री ने ओडिशा को 1700 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की सौगात दी है

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को झारसुगुड़ा के एक दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा के आमपाली पौडिया में आयोजित एक जनसभा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने ओडिशा को 1700 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की सौगात दी है। 160,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। देश भर में 97,500 से अधिक दूरसंचार टावर चालू हैं। बरहामपुर और सूरत के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। संबलपुर सिटी और सरला के बीच रेलवे फ्लाईओवर का शिलान्यास

किया गया। कोरापुट-बैंगुड़ा रेलवे लाइन और मनाबार-कोरापुट-गोरपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का उद्घाटन किया गया। भुवनेश्वर में सेमीकंडक्टर और इंएसडीएम पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी गई। राज्य सरकार की वैश्विक कौशल विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया।

राज्य के 130 उच्च शिक्षण संस्थानों में वाईफाई सेवाओं का उद्घाटन किया गया। भीमसर और एमकेसीजी कॉलेजों के उन्नयन के लिए तैयार मास्टर प्लान का उद्घाटन किया गया। उन्होंने अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 परिवारों के लिए घरों के निर्माण को मंजूरी दी। उन्होंने देश के 8 आईआईटी की क्षमता निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। इसी तरह, मोदी ने पूरे देश में 4जी सेवाएँ शुरू की हैं।



'एक शाम मां भगवती के नाम' जागरण सम्पन्न

जगदीश सीरवी

हैदराबाद घटकेसर कोरेमुला स्थित श्री आईमाताजी मंदिर (बडेर) के तत्वावधान में 'एक शाम मां भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया गया। आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञापित में संरक्षक प्रभुराम परिहारिया, अध्यक्ष कालुराम काग, सचिव डायराम लचेटा ने बताया कि डॉडिया नृत्य व जागरण आयोजित किया गया। श्री आईमाताजी मंदिर बडेर में प्रांगण में मां भगवती का विशाल पंडाल सजाकर तत्पश्चात् पूजा अर्चना व ज्योत प्रज्वलित कर जागरण का आयोजन किया गया। अक्सर पर गणेश वंदना के साथ भजन गायिका सीता माली एण्ड पार्टी बालोतरा जोधपुर राजस्थान, भजन गायक जैतु प्रजापत ने राजस्थानी लोक भजनों की प्रस्तुतियाँ दीं। भजनों पर श्रद्धालु भावविभोर होकर झूमते रहे। कार्यक्रम में पंथी सर्व समाज के गणमान्य पदाधिकारियों अखिल भारतीय सीरवी महासभा तेलंगाना प्रदेश सचिव सोहनलाल हाम्बड़ सीरवी समाज पारसीगुटा बडेर अध्यक्ष मोहनलाल हाम्बड़, श्री आईजी गौशाला अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, सचिव हुकमाराम सानपुरा, सह सचिव दगलाराम सेपटा, कोषाध्यक्ष

नारायणलाल परिहार, सहलाकर भंवरलाल मुलेवा, श्री आईजी सेवा संघ चिरियाल अध्यक्ष भगाराम मुलेवा, सीरवी समाज मल्लापुर बडेर अध्यक्ष तुलसाराम सिन्दडा, पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल मुलेवा अतिथियों का समाज बन्धु के पदाधिकारियों ने शाल, दुपट्टा से विशेष सम्मान किया। महा प्रसादी की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर की गयी। संरक्षक प्रभुराम परिहारिया, अध्यक्ष कालुराम काग ने समाज बन्धु को नवरात्रि की शुभकामनाएँ देते हुए कार्यक्रम में संरक्षक प्रभुराम परिहारिया, अध्यक्ष कालुराम काग, उपाध्यक्ष 1 वगताराम पंवार, उपाध्यक्ष 2 राजाराम पंवार, सचिव डायराम लचेटा, सह सचिव राजाराम गेहलोत, कोषाध्यक्ष पोकराम पंवार, खेल मंत्री ओमप्रकाश हाम्बड़, सलाहकार पुनाराम हाम्बड़, रमेश हाम्बड़, समस्त कार्यकारिणी सदस्य, नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। मंच का संचालन सचिव डायराम लचेटा ने किया। कार्यक्रम का विशेष कवरेज पत्रकार जगदीश सीरवी ने किया। महाआरती व अध्यक्ष कालुराम काग व सचिव डायराम लचेटा के धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम का समापन हुआ।



दुर्गापूजा को लेकर सरायकेला उपायुक्त का जमशेदपुर के निकट अन्तिम बैठक

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड

सरायकेला, जमशेदपुर औद्योगिक शहर के निकट इंडस्ट्रियल वेल्ड आदित्यपुर में दुर्गा पूजा और दशहरा शांति सन्मन कराने को लेकर जिला प्रशासन परेड आरंभ कर दिया है। शनिवार को जिले के पदाधिकारियों संग आर्टो क्लस्टर सभागार में डीसी और एसपी ने अंतिम बैठक की और आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बैठक में निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण डॉ. अजय तिकी, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, अपर नगर आयुक्त, आदित्यपुर नगर निगम रवि प्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला निवेदिता निर्यति, प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा अविनाश कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर डीसी नितिश कुमार सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व के दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपने-अपने स्थल पर पूर्ण संवेदनशीलता एवं सतर्कता के साथ तैनात रहें। सोशल मीडिया पर पैनी निगरानी रखते हुए अफवाह अथवा भ्रामक समाचार के प्रसार को रोकना सुनिश्चित करें। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन हेतु यातायात व्यवस्था एवं वाहन पार्किंग को सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाए। सभी पूजा पंडाल समितियों पंडाल परिसर में साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, अनिशमन यंत्र एवं प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएँ। प्रत्येक पंडाल में महिला एवं पुरुष



श्रद्धालुओं के लिए पृथक प्रवेश एवं निकास द्वार हों तथा आपातस्थिति हेतु वैकल्पिक निकास अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। रावण दहन एवं विसर्जन केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित समय, मार्ग एवं चिह्नित स्थलों पर ही संपन्न किया जाए। 2 अक्टूबर को ड्राई-डे घोषित रहेगा तथा जिले की सभी मद्यपान दुकानें बंद रहेंगी। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि सभी एम्बुलेंस चिह्नित स्थलों पर तैनात रहें और चिकित्सा दल सक्रिय मोड में उपलब्ध हों।

यह भी कहा कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का प्रत्येक समिति एवं संबंधित पदाधिकारी द्वारा अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित समिति अथवा पदाधिकारी विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होंगे।

साथ ही उन्होंने सभी जिलेवासियों को आगामी दुर्गा पूजा एवं दशहरा की शुभकामनाएँ दीं और अपील की कि यह पर्व सौहार्द, भाईचारे एवं शांति-व्यवस्था के साथ मनाएँ तथा प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। एसपी मुकेश लुणाथ ने अपने संबोधन में कहा कि दुर्गा पूजा एवं दशहरा के दौरान पुलिस बल की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा होगी। उन्होंने कहा कि 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों में नो-एंट्री जोन प्रभावी रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक स्थानों पर वाहन पार्किंग नहीं हो तथा निर्धारित पार्किंग स्थलों पर कतारबद्ध पार्किंग सुनिश्चित की जाए। सर्विस रोड पर अनधिकृत दुकानों एवं ठेले लगाने की अनुमति नहीं होगी।

पंजाब पुलिस ने यूएई से बीकेआई आतंकी परमिंदर सिंह पिंडी को प्रत्यर्पित कर भारत लाया

— पिंडी हरविंदर रिंडा और हैप्पी पासिया का करीबी सहयोगी; कई जघन्य अपराधों में शामिल: डीजीपी गौरव यादव

— डीजीपी पंजाब ने विदेश मंत्रालय, यूएई सरकार, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का अमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद किया

— बटाला पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए पिंडी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया: एसएसपी बटाला सुहेल कासिम मीर

चंडीगढ़/बटाला, 27 सितंबर (साहिल बेरी)

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को एक बार फिर सिद्ध करते हुए, पंजाब पुलिस ने बाबर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) मॉड्यूल के वांछित आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी से भारत प्रत्यर्पित करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के घनिष्ठ समन्वय एवं सहयोग से संभव हुई,



यह जानकारी पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शनिवार को दी।

जानकारी के अनुसार, बटाला के हरशा गांव का रहने वाला परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि एक खतरनाक आतंकी-क्रिमिनल सिंडिकेट का अहम सदस्य है। बटाला पुलिस की टीम आरोपी को भारत लेकर आई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पिंडी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा और हैप्पी पासिया के साथ मिलकर आतंकी है और बटाला-गुरदासपुर क्षेत्र में पेट्रोल बम हमले, हिंसक वादतों और रंगदारी जैसे कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। आरोपी सोशल

मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपराधों की योजना बनाने और उनके लिए फंड जुटाने का काम करता था।

उन्होंने बताया कि बटाला पुलिस के अनुरोध पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय विशेष टीम 24 सितंबर 2025 को यूएई गई। टीम ने विदेश मंत्रालय और यूएई प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं और आरोपी को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया।

यह सफल प्रत्यर्पण पंजाब पुलिस को आतंकवाद और संगठित अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, उन्नत जांच क्षमताओं और वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। डीजीपी ने

कहा, “हम विदेश मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात सरकार, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अमूल्य सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी मदद से यह संयुक्त अभियान सफल हो सका।”

अधिक जानकारी साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बटाला सुहेल कासिम मीर ने कहा कि पिंडी द्वारा किए गए गंभीर अपराधों और पाकिस्तान आधारित आतंकियों हरविंदर रिंडा और हैप्पी पासिया से उसके सीधे संबंधों को देखते हुए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। यह वैश्विक अलर्ट उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने और अबू धाबी में उसकी लोकेशन का पता लगाने में निर्णायक साबित हुआ।

एसएसपी ने कहा कि परमिंदर पिंडी की गिरफ्तारी के साथ पंजाब पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क के अहम टुकड़ों को ध्वस्त किया है। यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि कानून की लंबी पहुंच भौगोलिक सीमाओं से परे है।

इस बीच, सीबीआई ने बताया कि भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में, वह भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ “भारतपोल” प्रणाली के जरिए समन्वय करती है।

भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा के अमृतसर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री ईटीओ ने किया भव्य स्वागत



अमृतसर, 27 सितंबर (साहिल बेरी)

आज जालंधर से चलकर अमृतसर पहुंचे भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा का स्वागत कैबिनेट मंत्री श्री हरभजन सिंह ईटीओ ने गोल्डन गेट पर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज समय की मुख्य आवश्यकता है कि हम भगवान वाल्मीकि जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें और उनकी शिक्षाओं का पालन करें, तभी हम अपने जीवन को

सुखी और सफल बना सकते हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव राज्य स्तर पर अमृतसर में मनाया जाएगा। इस मौके पर श्री विपिन सबवाल, डीएसपी नीरज कुमार, श्री विकी चौदा, श्री पवन दराविड, श्री कुमार दर्शन, श्री शांति गिल के अलावा बड़ी संख्या में संगत मौजूद थीं।

प्रतिभा पलायन को रोकने का बड़ा मौका

प्रो. महेश चंद गुप्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। पहले जहां यह फीस लगभग 80 हजार रुपये थी, वहीं अब इसे 80 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। स्वाभाविक है कि अब पहले जितनी संख्या में भारतीय युवा अमेरिका नहीं जा पाएंगे। इस फैसले से दुनिया भर में उथल-पुथल मची है जिसका फायदा उठाने की कोशिश चीन कर रहा है। उसने ‘के वीजा’ नामक नई श्रेणी की घोषणा की है जिसके तहत वह दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी प्रोफेशनल्स को अपने यहां आकर्षित करना चाहता है। यह वीजा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तकनीक और व्यवसाय के क्षेत्र में अक्सर उपलब्ध कराएगा।

भारत के लिहाज से यह स्थिति एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों लेकर आई है। चुनौती इसलिए क्योंकि अमेरिकी दरवाजे बंद होने के बाद चीन नए अवसर देकर हमारी प्रतिभाओं को अपने यहां खींच सकता है। अक्सर इसलिए है क्योंकि यह भारत के लिए प्रतिभा पलायन रोकने का सुनहरा मौका है। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार, उद्योग जगत और कॉर्पोरेट सेक्टर मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां हमारे युवा देश में रहकर ही अपने सपनों को साकार कर सकें। भारत हमेशा से ही शिक्षा और प्रतिभा के मामले में समृद्ध रहा है पर प्रतिभा पलायन हमारी बड़ी समस्या है। हर साल लाखों छात्र-छात्राएं इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और रिसर्च के क्षेत्र में पढ़ाई पूरी

करते हैं लेकिन अफसोस है कि उनमें से बड़ी संख्या में युवा विदेशों का रुख कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में शोध के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, रोजगार के अवसर सीमित हैं और जो अवसर उपलब्ध हैं, उनमें योग्य प्रतिभा को सम्मान और सुरक्षा का अभाव है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और आईटी प्रोफेशनल विदेश जाकर वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जबकि उनकी प्रतिभा का लाभ भारत को मिलना चाहिए। एक तरफ हम युवाओं की शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, दूसरी ओर वे अक्सरों की कमी के कारण देश छोड़ जाते हैं। यह भारत के विकास के लिए बड़ी हानि है। ट्रंप का वीजा फीस वृद्धि का कदम दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का विषय हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि भारत को इसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। जब अमेरिका में वीजा इतना महंगा हो गया है कि आम युवा वहां नहीं जा पाएंगे तो इससे स्वाभाविक रूप से प्रतिभा पलायन पर अंकुश लगेगा। यह स्थिति भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इस मौके का उपयोग भारत कर पाएगा? अगर सरकार और उद्योग जगत ने युवाओं के लिए बेहतर मौकें तैयार किये तो वे भारत में ही रहकर काम करना पसंद करेंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह संभावना है कि निराश युवा चीन की ओर आकर्षित हो जाएं।

चीन ने हालात को भांपते हुए तेजी से ‘के वीजा’ का विकल्प प्रस्तुत किया है। इस वीजा के माध्यम से वह दुनिया भर की प्रतिभाओं को अपने यहां शिक्षा, रिसर्च और बिजनेस में अवसर देने की योजना बना रहा है। ऐसा करके वह वैश्विक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नेतृत्व के अपने लक्ष्य को पूरा करने की तमना रखता है। यदि भारतीय युवा अमेरिका के बजाय चीन का रुख करने लगे तो यह हमारे लिए और भी गंभीर स्थिति होगी क्योंकि एक तरफ तो भारत अपनी ही प्रतिभा से वंचित रह जाएगा और दूसरी ओर चीन हमारी ही ताकत का उपयोग करके आगे निकलने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में हमें गहरा आत्म चिंतन की जरूरत है। इस समय यह बड़ा सवाल है कि क्या हमारे युवा विदेशों में ही अपनी क्षमता साबित करेंगे या फिर देश में रहकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? इसका उत्तर देश की नीतियों और कार्यप्रणालियों पर निर्भर करता है।

वर्तमान में विश्व की टॉप 100 कॉर्पोरेट कंपनियों में उच्च पदों पर हमारे युवा हैं, जो उनके कामकाज को पूरे विश्व में फैलाने में सहायक हो रहे हैं। सुंदर पिचई (गूगल), सत्य नडेला (माइक्रोसॉफ्ट), अजय बंगा (विश्व बैंक), अरविंद कृष्णा (आईबीएम) और इंद्रा नूई (पेप्सीको) जैसे दिग्गज भारतीय मूल के लोगों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता यह साबित करती है कि भारतीय मस्तिष्क वैश्विक स्तर पर किसी से कम नहीं है। सवाल यह है कि अगर प्रतिभावान युवाओं को देश में ही जरूरत अवसर और वातावरण मिल जाता तो क्या वे यहीं रहकर भारत को विश्व का नेतृत्व दिला सकते थे? इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से हाँ में है।

बाढ़ पीड़ितों की सेवा सरकार की पहली प्राथमिकता : जसविंदर सिंह रमदास

अमृतसर, 27 सितंबर (साहिल बेरी)

आम आदमी पार्टी के अटारी हलके से विधायक जसविंदर सिंह रमदास ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों की सेवा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता मान रही है।

रमदास ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सरकार की ओर से तुरंत राहत और सहायता कार्य शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वे घर-घर जाकर लोगों की परेशानियां सुनें और मौके पर ही उनका समाधान करें। विधायक ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी सेवक और साथी जमीनी स्तर पर लोगों के साथ खड़े हैं और सरकारी मशीनों के साथ मिलकर पीड़ित परिवारों तक



सहायता पहुंचा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुनर्वास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है और किसी भी परिवार को सरकारी सुविधाएं या राहत सामग्री देने में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी।

रमदास ने पशुओं में बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे

प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पशुपालक परिवारों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इस दिशा में भी पूरी तरह ध्यान दे रही है।

एमएलए रमदास ने मुख्यमंत्री की ओर से बाढ़ पीड़ित किसानों को मुफ्त गेहूं का बीज बांटने के फैसले की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों की आर्थिक राहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और कृषि की पुनर्हाली में बड़ा योगदान देगा। रमदास ने कहा, “सरकार और आम आदमी पार्टी का हर सेवक लोगों की सेवा में तत्पर है। किसी को भी खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है, पूरी सरकारी मशीनरी हमेशा लोगों के साथ खड़ी है।”

शहर की सफाई व्यवस्था को बढ़िया बनाया जाएगा: विधायक डॉ अजय गुप्ता, कहा, कंपनी के काम छोड़ने से सफाई को लेकर कुछ दिक्कत आई

अमृतसर, 27 सितंबर (साहिल बेरी)

केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ अजय गुप्ता द्वारा अपनी टीम के साथ शुरू किया गया सफाई अभियान लगातार आज जारी रखा। आज विधायक डॉ गुप्ता ने गेट खजाना से भद्रकाली मंदिर के आसपास के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था करवाई। विधायक डॉ गुप्ता ने कहा कि नगरात्रों के शुरू होते ही उनके द्वारा अपनी टीम के साथ शहर में सफाई अभियान शुरू करवाया था, जो लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी के काम बीच में ही छोड़ने से सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ दिक्कत आई हैं। उन्होंने कहा इसके बावजूद मेयर जितेंद्र सिंह मोती भाटिया, नगर निगम के कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल, निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी निगम की सारी मशीनरी और प्राइवेट ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर से प्रतिदिन लगभग 560 मेट्रिक टन कूड़ा कचराक उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र में लगातार वह खुद सड़कों पर उतरकर सफाई व्यवस्था करवा रहे हैं।

विधायक डॉ गुप्ता ने कहा कि अवर्षा कंपनी द्वारा पहले से ही सफाई



व्यवस्था को लेकर कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यह सब पिछली सरकारों की देन है। उन्होंने कहा कि अवर्षा कंपनी के साथ पिछली अकाली भाजपा सरकार ने साल 2016 में कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्होंने कहा कि ठीक पर प्रबंध न होने पर कंपनी एग्जिट कर गई। कंपनी द्वारा अबूबर महीने में कार्य बंद करना था। किंतु कंपनी ने 5 अगस्त को ही कार्य बंद कर दिया गया। जिससे सफाई व्यवस्था को लेकर समस्या आई।

विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा

कि नगर निगम द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नई कंपनी को लाने के लिए पिछले 6 महीनों से एस्टीमेट बनवाकर टेडर प्रक्रिया में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में नई कंपनी को वर्क आर्डर अलाट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नई कंपनी द्वारा कार्य शुरू करने पर गुरु नगरी अमृतसर की सफाई व्यवस्था बेहतरीन हो जाएगी। आज के सफाई अभियान में निगम अधिकारी, सफाई सेवक और भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स मौजूद थे।

हर सफल व्यक्ति में किस प्रकार की मानसिकता आम होती है?

आगे रहने के लिए किसी और को पीछे मत धकेलें। ज्यादातर सफल लोग मनचाही जगह पाने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते; बल्कि अपनी प्रतिभा, लगन और जुनून पर भरोसा करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे जानते हैं कि अनुकूल परिणाम पाने के लिए स्वस्थ तरीके से कैसे प्रतियोगिता करनी है। प्रचुरता की मानसिकता। सफल लोग मानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हर किसी के पास पर्याप्त संसाधन अवसर हैं। बस उन्हें इनका कुशलतापूर्वक उपयोग करने की जरूरत है। असफलता और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उस सिक्के को सफलता कहते हैं। हर सफल व्यक्ति जानता है कि जीवन में

सफलता पाने के लिए, उसे असफल होने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सफलता बस समय की बात है। ज्यादातर भरोसा करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे जानते हैं कि अनुकूल परिणाम पाने के लिए स्वस्थ तरीके से कैसे प्रतियोगिता करनी है। प्रचुरता की मानसिकता। सफल लोग मानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हर किसी के पास पर्याप्त संसाधन अवसर हैं। बस उन्हें इनका कुशलतापूर्वक उपयोग करने की जरूरत है। असफलता और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उस सिक्के को सफलता कहते हैं। हर सफल व्यक्ति जानता है कि जीवन में

हर कोशिश अधूरी रहेगी और कभी भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। हालांकि, जब जुनून आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है, तो आप अपनी मनचाही चीज पाने के लिए त्याग करने और अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार रहते हैं, और साथ ही अपने काम का आनंद भी लेते हैं। भले ही यह कभी-कभी मुश्किल हो। किसी नतीजे से आसक्त न हो, धीरे-धीरे अपना धैर्य और आत्मविश्वास कम हो जाता है। हालांकि, सफल लोग नहीं होते; उन्हें खुद पर पूरा विश्वास होता है और उनमें जबदस्त धैर्य होता है, जो उन्हें मुश्किल से मुश्किल समय में भी धार न मानने की ताकत देता है। आप जो करते हैं उसके प्रति जुनून रखें। सफल लोग जानते हैं कि अगर आपमें किसी चीज के प्रति जुनून नहीं है, तो आपकी

मेडिकल कैंप : डायोसिस ऑफ अमृतसर, CNI ने तलवंडी रामा गाँव में लगाया मुफ्त मेडिकल कैंप

अमृतसर, 27 सितंबर (साहिल बेरी)

अमृतसर के आसपास के बाढ़ प्रभावित गाँवों को राहत प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, डायोसिस ऑफ अमृतसर, CNI के टर्निंग पॉइंट प्रोजेक्ट ने तलवंडी रामा गाँव में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया।

इस मेडिकल कैंप में आसपास के गाँवों से आए 300 से अधिक लोगों की जांच की गई। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने इस कैंप में भाग लिया और ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, बाल रोग और गायनेकोलॉजी सहित व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कीं।

अमृतसर डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन के सचिव श्री डेनियल बी. दास ने कहा, “कैंप में मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच शामिल थी, और उपस्थित लोगों को मुफ्त दवाइयाँ वितरित की गईं।”

डायोसिस ऑफ अमृतसर, CNI के बिशप और एक्टिव डिप्टी मॉडरेटर द राइटर रेवेरेन्ड मनोज चरण ने कहा, “डायोसिस ऑफ अमृतसर का उद्देश्य सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करते हुए कमजोरियों को दूर



करना और क्षमताओं को बढ़ाना है। यह मेडिकल कैंप उस लक्ष्य को हासिल करने और लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डायोसिस ऑफ अमृतसर, CNI की

विकास अधिकारी श्रीमती सोनिया सामंतराय, जिन्होंने इस कैंप का आयोजन किया, ने कहा, “इस पहल का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना है।”

डायोसिस ऑफ अमृतसर के सम्मानित अतिथि रेवेरेन्ड अश्वेक डेनियल, डॉ. एम्ना राम, रेवेरेन्ड डॉ. पुलक सामंतराय और रेवेरेन्ड पवन पाल ने भी मेडिकल कैंप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।